राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • सोमवार • 10 मार्च • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

जो स्वयं संयमित व नियंत्रित है, उसे व्यर्थ में और अधिक नियंत्रित नहीं करना चाहिए, जो अभी अनियंत्रित है, उसी को नियंत्रित किया जाना चाहिए।
-अथर्व वेद

कहते तो हैं, करते नहीं

गुजरात में अपनी ही पार्टी के नेताओं पर राहुल गांधी का गुस्सा जताना कई सवाल खड़े करता है। राहुल शनिवार से दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और उन्होंने दूसरे दिन पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के भीतर दो गुट नजर आ रहे। आधे लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हटाने की सख्त कार्रवाई करनी पड़ी तो जरूर की जानी चाहिए। ऐसा कह कर राहुल ने उन नेताओं को भी सख्त संदेश देने की कोशिश की है जो हमेशा पार्टी हित के खिलाफ काम करते हैं, और पार्टी को गर्त में पहुंचाने में उनकी महती भूमिका है। दरअसल, राहुल गांधी का गुस्सा जायज है। पार्टी करीब 30 साल से गुजरात में सत्ता से बाहर है। उसके कई नेता पार्टी का साथ छोड़ कर भाजपा का दामन थाम चुके हैं।

पिछली बार (2022) के चुनाव में भाजपा ने जहां 156 सीट जीत कर अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया था, वहीं कांग्रेस को महज 17 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। गौरतलब है कि साल 2027 में वहां विधानसभा के चुनाव होंगे। राहुल उसी के मद्देनजर दांव चल रहे हैं। यह मंशा उनके इस बयान से भी जुड़ती दिखती है, जब वो यह कहते हैं, 'यहां विपक्ष के पास 40 फीसद वोट हैं। यहां विपक्ष छोटा नहीं है। अगर गुजरात के किसी भी कोने में दो लोगों को आप खड़ा कर देंगे तो उनमें से एक बीजेपी का और दूसरा कांग्रेस का निकलेगा यानी दो में से एक हमारा, एक उनका होगा।' 'लेकिन हमारे मन में है कि कांग्रेस के पास दम नहीं है। अगर गुजरात में हमारा वोट पांच फीसद बढ़ जाएगा तो आप (बीजेपी) वहीं खत्म हो जाओगे।' हालांकि, उनका ऐसा कहना पूरी तरह से सही भी नहीं कहा जा सकता है। पिछले साल संपन्न महाराष्ट्र, हरियाणा के चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन दोनों ही जगह उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार, बंगाल सभी जगहों पर पार्टी कई गुटों में बंटी नजर आती है। इस वजह से उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नजर नहीं आता। पार्टी में इस गुटबाजी से निपटने के लिए कांग्रेस नेतृत्व में कई बार मंथन हुआ। उदयपुर के चिंतन शिविर में इसे लेकर राज्य स्तर पर प्रदेश समन्वय कमेटी बनाने का फैसला किया गया था। हालांकि, इस पर कितना अमल हुआ यह पार्टी नेतृत्व को भी बखूबी पता है। दूसरी अहम बात यह कि आला कमान के स्तर पर भी अपने-अपने गुट हैं। राहुल गांधी का अलग तो प्रियंका का अलग। ऐसे में सिर्फ नेताओं को दोषी ठहराना न्यायसंगत नहीं है।

महिला सम्मान से समृद्धि

भाजपा की दिल्ली सरकार ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता के लिए 51 करोड़ रुपये सालाना की महिला समृद्धि योजना पर मुहर लगा दी। इस योजना के तहत पात्रों के बैंक खातों में हर महीने 2500 रुपये भेजे जाएंगे। योजना में पारदर्शिता के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद और कपिल मिश्र इसके सदस्य होंगे। दिल्ली विधानसभा के हाल में संपन्न चुनाव में भाजपा ने इस बाबत गारंटी दी थी। इस प्रकार कहें तो भाजपा ने अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है।

अलबत्ता, इसके लिए पात्रता संबंधी कुछ शर्तें भी हैं, जिन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि चुनाव के समय सहजता से दी गई गारंटी को लागू करने के समय दिल्ली में 27 साल बाद सत्तारूढ़ हुई भाजपा को वास्तविकता का भान हुआ। यह कि चुनावी घोषणा को क्रियान्वित करने में खासा वित्तीय बोझ सरकार पर पड़ने वाला है। विपक्षी 'आप' महिला समृद्धि योजना की घोषणा में विलंब को लेकर सरकार की आलोचना में जुट गई थी। हर संभव तरीके से जतलाने में जुट चुकी थी कि भाजपा की यह गारंटी महज चुनावी जुमला साबित हो सकती है। भाजपा ने महिला दिवस के अवसर पर विपक्ष की पैंतरेबाजी को फिलहाल तो नाकाम कर दिया है। लेकिन अभी देखा जाना है कि योजना से लाभान्वित होने संबंधी औपचारिकताएं पूरा करने में महिलाओं को कितनी आसानी रहेगी। कमेटी बनाई गई है कि पात्रता संबंधी दिक्कतें दरपेश न होने पाएं जबकि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कमेटी गठित किए जाने को योजना को ठंडे बस्ते में डाल देने की कवायद करार देकर भाजपा सरकार की चिंता बढ़ाने का काम किया है। वे यह भी दावा कर रही हैं कि पीएम नरेन्द्र मोदी की चुनाव के समय दी गई इस बाबत गारंटी एक धोखा साबित हो सकती है। बेशक, जो शर्तें रखी गई हैं उन्हें देखते हुए इतना तो कहा ही जा सकता है कि इस योजना के कार्यान्यन में अभी समय लगना पक्का है। आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना और पैन कार्ड होने की अनिवार्यता ऐसी शर्तें से जिनके चलते योजना की पात्रता हासिल करने में समय लग सकता है। बहरहाल, आर्थिक सशक्तिकरण का यह कदम महिला उत्थान की दिशा में स्वाग्ययोग्य फैसला है।

सामयिक/प्रो. आर.के. जैन 'अरिजीत'

धैर्य का डेटा खत्म

एक समय था जब प्रतीक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, धैर्य की कसौटी थी, और जीवन का अभिन्न अंग थी। यह प्रतीक्षा भी अपने आप में अनुभव होती थी-नये लोगों से बातचीत करने, अखबार के पन्नों में खो जाने, या फिर बस यूं ही समय के प्रवाह को महसूस करने का। लेकिन आज, यह धैर्य क्षीण हो गया है। अब 'लोड हो रहा है कृपया प्रतीक्षा करें...' की झलक मात्र से अधीरता सिर उठाने लगती है। लोग इंतजार को व्यर्थ समझने लगे हैं, सब कुछ तुरंत चाहिए। तकनीक ने जहां सुविधाएं बढ़ाई हैं, वहीं धैर्य की परिभाषा को भी बदल दिया है।

एक दौर था जब लोग सड़क किनारे खड़े होकर घंटों बस का इंतजार किया करते थे। धैर्य की मूर्ति बने खड़े रहते, बस आई तो ठीक, वरना अगली के इंतजार में चेहरे पर वही संतोष की मुस्कान। पहले चिट्ठी लिख कर जवाब के लिए महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। कबूतर उड़ाने की जरूरत नहीं थी, डाकिया खुद ही संदेशा ले आता था, भले ही साथ में बिन मांगे बिजली-पानी के बिल भी थमा जाता। अब व्हाट्सएप पर 'ब्लू टिक' लगने के बाद भी जवाब न आए तो धड़कनें बढ़ जाती हैं। पहले प्रतीक्षा सहनशीलता की निशानी थी, अब मानसिक संतुलन की परीक्षा। पहले शादी-ब्याह में रिश्तेदारों के आने की प्रतीक्षा होती थी। अब बारातियों से ज्यादा फूड डिलीवरी वाले का इंतजार होता है। पहले टीवी पर रविवार को रामायण-महाभारत के लिए पूरा मोहल्ला इंतजार करता था। अब ओटीटी पर वेब सीरीज का 'अगला एपिसोड' लोड होने में दस सेकंड लग जाएं तो लोग अपना इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने लगते हैं। कभी सड़क पर साइकिल की सवारी के दौरान भी इंतजार करना पड़ता था-गड्ढे में से बैलगाड़ी निकल जाए तब आगे बढ़ो। अब सिग्नल पर पांच सेकंड की लाल बत्ती भी लोगों को असहनीय लगती है। पीछे से हॉर्न बजाने वाले ऐसे बर्ताव करते हैं मानो जरा-सा और रुके तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर देगी। प्रगति के इस युग में हम जितना तेज हुए हैं, हमारे लिए इंतजार करना भी उतना ही असहनीय हो गया है। बेशक, तकनीक ने गति दी है, लेकिन हमारे धैर्य की बत्ती गुल कर दी है। 'लोड हो रहा है कृपया प्रतीक्षा करें...' देखना अब किसी हॉरर फिल्म से कम डरावना नहीं लगता। समय बदला है, मगर सवाल वही है-सब्र का प्याला अब इतनी जल्दी क्यों छलकने लगा है?

श्मशान घाटों का कायाकल्प

सामयिक

विनीत नारायण

मौत कैसी भी क्यों न हो परिजनों को भारी पीड़ा देती है। घर का बुजुर्ग भी अगर चला जाए तो एक ऐसा शून्य छोड़ जाता है, जो फिर कभी भरा नहीं जा सकता। उसकी उपस्थिति का कई महीनों तक परिवारजनों को आभास होता रहता है। उसकी दिनचर्या को याद कर परिजन दिन में कई बार आंसू बहा लेते हैं। घर में कोई उत्सव, मांगलिक कार्य या अनुष्ठान हो तो अपने बिछुड़े परिजन की याद बरबस आ जाती है। जब मृतकों की स्मृति के लिए इतना कुछ किया जाता है, तो जब कोई अपना जीवन समाप्त कर अंतिम यात्रा को प्रस्थान करता है, उस समय परिजनों के हृदय की व्यथा शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती।

घर में जैसे ही मौत होती है, पहली प्रतिक्रिया तो आघात की होती है। सारा परिवार महाशोक में डूब जाता है। फिर तुरंत ही अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू कर दी जाती है। जीते जी हम अपने प्रियजन को कितना ही प्यार क्यों न करते रहे हों, उसकी मौत के बाद शव को कोई बहुत समय तक घर में नहीं रखना चाहता। अर्थी सजाने से लेकर श्मशान जाने तक का कार्यक्रम बहुत व्यस्त कर देने वाला होता है। जहां घर की महिलाएं रुदन और विलाप में लगी होती हैं वहीं पुरुष सब व्यवस्था में जुट जाते हैं। अपनी क्षमता और भावनानुसार लोग अपने प्रियजन की इस अंतिम यात्रा को अधिक से अधिक भव्य बनाने का प्रयास करते हैं। श्मशान घाटों की दुर्दशा पर बहुत समाचार नहीं छपते। यह एक गंभीर विषय है, और आश्चर्य की बात है कि मरते सब हैं पर मौत की बात करने से भी हमें डर लगता है।

जब तक किसी के परिवार में ऐसा हादसा न हो वह शायद ही श्मशान तक कभी जाता है। उस मौके पर शवयात्रा में आए लोग श्मशान की दुर्दशा पर बहस करने के लिए बहुत उत्साहित नहीं होते। जैसा भी व्यवहार मिले, सह कर चुपचाप निकल जाते हैं। पर एक टीस तो मन में रह ही जाती है कि हमारे प्रियजन की विदाई का अंतिम क्षण ऐसी अव्यवस्था में क्यों गुजरा? क्या इससे बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकती थी? प्रायः देश के शहरों में श्मशान घाट पर और उसके चारों ओर गंदगी का साम्राज्य होता है। जली लकड़ियां, बिखरे सूखे फूल, पहले आए शवों के साथ फेंके गए पुराने वस्त्र, प्लास्टिक के लिफाफे, अगरबत्तियों के डब्बे, घी के खाली डिब्बे, टूटे नारियल, टूटे घड़ों के ठीकरे जैसे तमाम सामान गंदगी फैलाए रहते हैं, जिन्हें महीनों कोई नहीं उठाता। उन पर पशु-पक्षी मंडराते रहते हैं। जहां शव लाकर रखा जाता है, वह चबूतरा प्रायः बहुत सम्माननीय स्थिति में नहीं होता। उसका टूटा पलस्तर और उस पर पड़ी पक्षियों की बीट जैसी गंदगी परिजनों का दिल तोड़ देती है। सबसे ज्यादा तो श्मशान घाट के व्यवस्थापकों का रूखा व्यवहार चुभता है। यह ठीक है कि नित्य

> दुर्भाग्य से हम हिन्दू होने का गर्व तो करते हैं पर अपने श्मशान घाटों को कसाईखाने की तरह चलाते हैं। हमारे समाज में श्मशान घाट का ऐसा विद्रूपी चेहरा शर्म की बात है। लेकिन इस मामले में आशा की किरण जगाई है देश के अनेक प्रांतों के कुछ शहरों के उन उत्साही दानवीर लोगों ने जिन्होंने सामान्य से भी आगे बढ़ कर श्मशान घाट को दर्शनीय स्थल बना दिया है। जामनगर, मथुरा, दिल्ली जैसे अनेक शहरों में यह कार्य बड़े पैमाने पर हुआ है

शवयात्राओं को संभालते-संभालते उनकी चमड़ी काफी मोटी हो जाती है, और भावनाएं शून्य हो जाती हैं, पर उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिन लोगों से उनका रोज सामना होता है, उनके लिए यह कोई रोज घटने वाली सामान्य घटना नहीं होती। टूटे मन, बहते नयन और बोझिल कदमों से चलते हुए लोग जब श्मशान घाट के व्यवस्थापकों से मिलते हैं, तो उन्हें स्नेह, करुणा, ढाढस और हर तरह के सहयोग की तत्परता का भाव मिलना चाहिए।

दुर्भाग्य से हम हिन्दु होने का गर्व तो करते हैं पर अपने श्मशान घाटों को कसाईखाने की तरह चलाते हैं जबकि पश्चिमी देशों में कब्रिस्तान तक जाने की यात्रा में चर्च और समाज की भूमिका अनुकरणीय होती है। वहां हर सामुदायिक केंद्र के पुस्तकालय में एक विशेष खंड ऐसी पुस्तकों का होता है, जिनमें मृत्यु से जूझने के नुस्खे बताए जाते हैं। यह तो पश्चिमी समाज की बात है जहां संयुक्त परिवार और शेष समाज अब आपके जीवन में दखल नहीं देते। पर भारतीय समाज में ऐसा शायद ही होता हो कि किसी के घर मौत हो और उसे स्थिति से अकेले निपटना पड़े। उसके नातेदार और मित्र बड़ी तत्परता से उस परिवार की सेवा में जुट जाते हैं, और कई दिन तक उस परिवार को सांत्वना देने आते रहते हैं। इसलिए हमारे समाज में श्मशान घाट का ऐसा विद्रूपी चेहरा तो और भी शर्म की बात है। पर ऐसा है, यह भी मृत्यु की तरह अटल सत्य है। इस मामले में आशा की किरण जगाई है देश के अनेक प्रांतों के कुछ शहरों के उन उत्साही दानवीर लोगों ने जिन्होंने सामान्य से भी आगे बढ़ कर श्मशान घाट को एक दर्शनीय स्थल बना दिया है। जामनगर, मथुरा, दिल्ली जैसे अनेक शहरों में यह कार्य बड़े पैमाने पर हुआ है। इसी संदर्भ में श्मशान घाटों को पर्यावरण की दृष्टि से विकसित किए जाने की नई पहल हरियाणा प्रांत में हुई है।

पिछले सप्ताह मुझे हरियाणा के एक आईएएस अधिकारी का संदेश आया जिसमें उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति केवल 1.33 पेड़ हैं, जबकि दाह संस्कार के लिए प्रति व्यक्ति 2 पेड़ों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कम लागत वाले ग्रीन शवदाहगृहों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा मानवाधिकार आयोग में एक याचिका दायर की और आयोग ने उनके पक्ष में ग्रीन शवदाहगृह बनाने के संबंध में आदेश जारी किया जो शरीर की वसा को 760 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने और फिर शरीर की वसा से शव का दाह संस्कार करने के लिए केवल 60 किलोग्राम जैव ईंधन का उपयोग करके एसपीएम, उत्सर्जन और राख को 85% तक कम करता है। यह अच्छी पहल है। उम्मीद है कि अब हरियाणा सरकार इस मुद्दे को उठाएगी जिससे दाह संस्कार की लागत 90% कम होकर मात्र 1100/-रुपये रह जाएगी। सिरसा, फतेहाबाद, भटिंडा, फाजलिका, अबोहर आदि में पहले से ही 750 से अधिक ऐसे हरित शवदाहगृह कार्य कर रहे हैं। यदि यह प्रयोग एक राज्य में कामयाब हो सकता है, तो भारत में सभी दाह संस्कार हरित शवदाहगृह में परिवर्तित हो सकते हैं। इन हरित शवदाह गृहों के निर्माण पर मात्र 4 लाख रुपये की लागत आती है, और इसे उसी चिता स्थान पर बनाया जा सकता है। इसका निर्माण ऐसा हो कि खराब मौसम में भी इसका उपयोग किया जा सके तथा दुर्गंध को भी दूर किया जा सके। राज्य और केंद्र की सरकारों को इस विषय पर ध्यान देने की जरूरत है जिससे कि दाह संस्कार के लिए हरित विकल्प के बारे में सोचा जा सके। यह सार्वजनिक हित का कार्य है अतः इसके लिए अपने क्षेत्र के सांसद और विधायकों की विकास राशि से भी मदद ली जा सकती है पर सरकारी धन पर निर्भर रहने से बेहतर होगा कि लोग निज प्रयासों से इस काम को पूरा करें।

(लेख में विचार निजी हैं)

खुजलाने के फायदे भी कम नहीं!

- त्वचा पर कहीं दाना निकल जाए या फिर मच्छर के काटने से उस जगह को रगड़ने का मन करे तो यह गलत नहीं है। एक हालिया रिसर्च यह दावा करती है। चूहों पर यह अध्ययन किया गया है
- पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय में त्वचा विज्ञान एवं प्रतिरक्षा विज्ञान के प्रोफेसर और वरिष्ठ अध्ययन लेखक डॉ. डैनियल कपलान का रिसर्च पेपर हाल में साइंस जर्नल में छपा है
- शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि कुछ मामलों में खुजलाना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जब खुजली पुरानी हो, तो नुकसान ज्यादा हो जाता है

(मीडिया इनपुट्स)

टैरिफ लगाने संबंधी ट्रंप की दो अप्रैल को दी गई धमकी का सामना करने के लिए भारत के पास क्या कोई कूटनीतिक योजना है? हम देख सकते हैं चीन और कनाडा की प्रतिक्रिया और इन तीन विकल्पों को-हार मान लें, पीछे हट जाएं या माकूल जवाब दें।

सुहासिनी हैदर, पत्रकार
@suhasinih

सुरक्षा व्यवस्था का अहम स्तंभ

सीआईएसएफ | अभिषेक गुप्ता

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)-10 मार्च, 1969 को स्थापित-भारतीय सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है। इस बल का उद्देश्य देश के महत्त्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, परमाणु संयंत्रों, मेट्रो स्टेशनों और अन्य राष्ट्रीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अत्याधुनिक तकनीक, कठोर प्रशिक्षण और अनुशासन के साथ सीआईएसएफ देश की सुरक्षा को अभेद्य बना रहा है।

सीआईएसएफ की विशेषज्ञता औद्योगिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है। यह बल देश के 66 से अधिक हवाई अड्डों, परमाणु संयंत्रों, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों, मेट्रो नेटवर्क और सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता है। इसके अलावा, सीआईएसएफ महत्त्वपूर्ण सरकारी और निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में भी तैनात है, जिनमें इस्पात संयंत्र, तेल रिफाइनरियां, बंदरगाह, जल विद्युत और थर्मल पावर प्लांट शामिल हैं। सीआईएसएफ का डॉग स्क्वाड दुनिया के सबसे उन्नत सुरक्षा बलों में माना जाता है। यह विस्फोटकों और अन्य संदिग्ध सामग्रियों की पहचान में अत्यधिक कुशल है। साथ ही, सीआईएसएफ स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम, बायोमेट्रिक सिस्टम, बॉडी स्कैनर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करता है, जिससे किसी भी खतरे का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सकता है। सीआईएसएफ न केवल सुरक्षा का प्रतीक है, बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी महत्त्वपूर्ण उदाहरण बन चुका है। इस बल में 7% से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं, जो इसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ में महिला भागीदारी के मामले में अग्रणी बनाता है। 2024 के गणतंत्र दिवस पर पहली बार सीआईएसएफ की महिला बैंड टुकड़ी और महिला कमांडो टुकड़ी ने कर्त्तव्य पथ पर मार्च किया। इस ऐतिहासिक परेड का नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट तन्मयी मोहंती ने किया था। इस प्रदर्शन ने प्रमाणित किया कि महिलाएं भारतीय सुरक्षा बलों में पुरुषों के समान योगदान देने में पूरी तरह सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त, नवम्बर, 2024 में गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ की पहली 'ऑल-वुमेन बटालियन' की

स्थापना को मंजूरी दी। इसमें 1,025 महिला कमांडो शामिल हुईं जिन्हें हवाई अड्डों, मेट्रो स्टेशनों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, वीआईपी सुरक्षा में तैनात किया जाएगा।

सीआईएसएफ का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे अन्य सुरक्षा एजेंसियों से अलग बनाता है। इसमें जवानों को क्राउड कंट्रोल, एंटी-टेरर ऑपरेशंस, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा, और उच्चस्तरीय खुफिया विश्लेषण का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण का केंद्र राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी है, जो हैदराबाद में है। यह अकादमी भारत ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रसिद्ध है। सीआईएसएफ आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान,सीआईएसएफकर्मियों ने लॉकडाउन के समय हवाई अड्डों और सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की। सीआईएसएफ की दक्षता भारत तक सीमित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के तहत सीआईएसएफ के अधिकारी कई अंतरराष्ट्रीय अभियानों में शामिल रहे हैं। इसके अलावा, सीआईएसएफ भारत के पर्यटन स्थलों की सुरक्षा में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ताजमहल, कुतुब मीनार, और अन्य ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा सीआईएसएफ के अधीन है, जिससे पर्यटकों को सुरक्षित और संरक्षित माहौल मिलता है। 20 मई, 2024 से सीआईएसएफ को संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। पहले यह कार्य केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ द्वारा किया जाता था। सीआईएसएफ की औद्योगिक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में विशेषज्ञता को देखते हुए यह महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। सीआईएसएफ ने स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम, बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल, बम-डिटेक्शन यूनिट और अन्य सुरक्षा उपाय अपना कर संसद भवन की सुरक्षा को अधिक अभेद्य बनाया है।

सीआईएसएफ एक सुरक्षा एजेंसी नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय संपत्तियों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर विकसित हो रहा बल है। इसकी कड़ी ट्रेनिंग, अत्याधुनिक तकनीक और अनुशासन इसे दुनिया के सबसे प्रभावी सुरक्षा बलों में से एक बनाते हैं। सीआईएसएफ का स्थापना दिवस बलिदान, अनुशासन और उत्कृष्टता का सम्मान करने का अवसर है। यह संगठन नई ऊंचाइयां छू रहा है, देश की सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें संकल्प लेना चाहिए कि इस गौरवशाली बल को और अधिक सशक्त बनाने के लिए हर संभव समर्थन देंगे। राष्ट्र की रक्षा में तत्पर सीआईएसएफ के हर कर्मी को हमारा नमन।

चरित्र | श्रीराम शर्मा आचार्य

समाज की सुव्यवस्था का आधार उज्ज्वल चरित्र के व्यक्तियों का बाहुल्य माना गया है। सुख-शांति और संतोष की परिस्थितियां नेक व्यक्तियों के सदाचार से बनती हैं। प्रेम, स्नेह, मैत्री, दया, आत्मीयता और सहानुभूति का वातावरण जहां भी रहेगा वहीं स्वर्ग जैसे सुखों की रसानुभूति होने लगती है। जो मनुष्य स्वभावतः दूसरों के साथ उदारता का व्यवहार करते हैं, स्नेह वृत्ति और परोपकार की भावना रखते हैं, वे अपने चरित्र की उज्ज्वल छाप दूसरों पर भी छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है तो ऐसे स्थान विशेष में स्वर्गिक परिस्थितियों का उभार स्वयमेव होने लगता है। व्यक्ति के चरित्रवान बनने से ही किसी समाज का सच्चा सुधार हो सकता है। इसलिए चरित्र की महान महत्ता को सभी महापुरुषों ने स्वीकार किया है। देखा जाता है कि लोग अपने बच्चों के नाम राम-कृष्ण, शिव-शंकर, राणा प्रताप, रणजीत आदि रखना अधिक पसंद करते हैं। रावण, कंस या खरदूषण नाम रखना किसी को भी प्रिय नहीं। इससे प्रतीत होता है कि लोगों में चरित्रवान की प्रतिष्ठा और सम्मान का भाव अधिक पाया जाता है। यह बात अपने यहां ही नहीं, बल्कि हर देश, जाति और संस्कृति में पाई जाती है। इससे चरित्र की महान महत्ता प्रतिपादित होती है। मनुष्य की कीर्ति, यश और सम्मान का आधार बाह्य जगत की सफलताएं नहीं हैं। उसकी आंतरिक श्रेष्ठता के आधार पर युगों तक यश शरीर अमर रहता है। दुराचारी व्यक्ति अपनी बाह्य-शक्तियों को भी देर तक बनाए नहीं रख सकते। कुकर्मों पर चलने से उनकी दुर्दशा स्वाभाविक है। फलतः उनका जीवन दिन-प्रतिदिन पतित होता जाता है, और उन्हें निरंतर नारकीय यंत्रणाएं भोगनी पड़ती हैं किंतु चरित्रवान व्यक्तियों को बुरा-समय भी वरदान सिद्ध हुआ है। अपनी चारित्रिक विशेषता के कारण सत्यव्रती हरिश्चंद्र ने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया था, उर्वशी का शाप कालांतर में अर्जुन के लिए वरदान सिद्ध हुआ। रावण के दुष्कर्मों का फल विनाश के रूप में मिला और विभीषण की नेकी का परिणाम यह हुआ कि उसे लंका की राजगद्दी मिली। चरित्र मनुष्य को सदैव ही ऊंचे उठाता है। इसलिए परिस्थितियों को चरित्रवान पुरुषों की चेरी कहा गया है।

रीडर्स मेल

शर्मसार करने वाली घटना

जब सारी दुनिया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की तैयारी कर रही थी तभी देवभूमि के नाम से जाने वाले हमारे देश को शर्मशार करने वाली घटना सुर्खियों में आई। यह शर्मनाक घटना विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कर्नाटक में हम्पी में हुई। यहां एक इस्राइली टूरिस्ट और एक होमस्टे की महिला ऑपरेटर के साथ कथित तौर पर सामूहिक रेप की घटना को अंजाम दिया गया। इससे पहले भी हमारे देश में ऐसी घटनाएं दूसरे पर्यटन स्थलों में हो चुकी हैं। विदेशी महिलाओं के साथ इस तरह की गलत हरकतें बढ़ती गईं तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश में दूसरे देशों से कोई पर्यटक महिला निडर होकर न घूमने आएगी और न ही वो अपने देश में रहते हुए कभी यह जिक्र करेगी कि भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित है। अगर हमारे देश में विदेशी पर्यटक आने से परहेज करेंगे तो जिन लोगों ने पर्यटक स्थलों पर अपना कोई होटल, ढाबा या अन्य कोई ऐसा कोई कारोबार, जो पर्यटकों से संबंधित है, तो प्रभावित होगा ही साथ ही विदेशी मुद्रा भी भारत में नहीं आएगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को चाहिए कि वो विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाएं ताकि विदेशी महिलाएं निडर होकर भारत घूमने फिरने आएं और वापस अपने देश जाकर इस बात की प्रशंसा करें कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे सुरक्षित देश है भारत...।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

वंशवादी राजनीति का विरोध करें

भारतीय लोकतंत्र में समय के साथ राजनीति में वंशवाद और परिवारवाद की समस्या गहराती जा रही है। राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्ति हो चुकी है, एवं नेतागण राजनीति के जरिए पद और धन की प्राप्ति करना चाहते हैं। कई क्षेत्रीय दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रहे हैं, जिनमें पार्टी की बागडोर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हाथों में हस्तांतरित हो रही है। पूर्व में जन आंदोलन के द्वारा नेता पैदा होते थे, लेकिन आज लोग परिवारवाद, बाहुबल और धनबल के सहारे राजनीति में आया करते हैं। परिवारवाद की राजनीति के वजह से योग्य कार्यकर्ता चुनावी टिकट से वंचित रह जाते हैं एवं आम जन को योग्य जनप्रतिनिधि नहीं मिल पाता है। आमजन को वंशवादी राजनीति का विरोध करना चाहिए एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए।

हिमांशु शेखर, गया

अपनी भूमिका समझे विपक्ष

आज देश को तमाम भीतरी एवं बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों से अपेक्षा की जाती है कि सरकार का अंधविरोध छोड़कर अपनी सार्थक भूमिका के साथ न्याय करें। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार के रचनात्मक विरोध की है ताकि वह सरकारी नीतियों की निगरानी एवं उन्हें जनोपयोगी बनाने में भूमिका निभाए। नीतियों पर सरकार को घेरें तो आवश्यक मुद्दों पर उसका सहयोग भी करें। ज्ञातव्य रहे कि 1962, 1965 और 1971 के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्धों में विपक्षी दलों ने खुले दिल से तत्कालीन केंद्र सरकारों का साथ दिया था, लेकिन आज उलटा दिख रहा है। कई बार तो विपक्ष की गतिविधियां चीन, पाकिस्तान जैसे बिगड़ैल पड़ोसियों का मनोबल बढ़ाने वाली होती हैं। क्या ऐसे में विपक्ष की भूमिका को सकारात्मक कहा जा सकता है?

मनोज श्रीवास्तव, सुलतानपुर

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
वर्ष-34, अंक 203
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काज़ी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 1209-1210, बाराखंबा मार्ग, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रमेश मिश्र*।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। सोमवार, 10 मार्च 2025

क्या चाहते हैं राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिस तरह की साफगोई दिखाई, उसे उनके किसी सामान्य बयान की तरह नहीं लिया जा सकता। सार्वजनिक तौर पर पार्टी नेताओं के एक हिस्से को विरोधी पार्टी से मिलीभगत का दोषी बताना किसी भी नेतृत्व के लिए जोखिम भरा काम है। कांग्रेस नेतृत्व ने यह जोखिम सोच-समझ कर ही उठाया होगा, लेकिन इसके पीछे वास्तव में उसकी कितनी तैयारी है, यह पार्टी के आगामी कदमों से स्पष्ट होगा।

अपने नेताओं पर आरोप

चुनावी नफा-नुकसान | राहुल गांधी के बयान की कुछ बातें खास तौर से ध्यान देने लायक हैं। मसलन- उन्होंने पार्टी की विचारधारा को सर्वोच्च कसौटी बनाने की बात कहते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि इसे वे चुनावी हार-जीत से जोड़कर न देखें। जाहिर है, उनकी नजर इस बात पर है कि कांग्रेस सही अर्थों में बीजेपी का विकल्प बनी रहे।

अन्य दलों से अलग | राहुल गांधी बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व की या बीजेपी की ही आलोचना तक खुद को सीमित नहीं रखते। वह बहस को सावरकर बनाम गांधी और संघ बनाम कांग्रेस की ओर ले जाने की कोशिश लगातार करते रहे हैं। विपक्षी ब्लॉक I.N.D.I.A. के अन्य दल और नेता इस मामले में उतने आक्रामक नहीं दिखते। इस लिहाज से अहमदाबाद में कही गई राहुल गांधी की बातें उनके दीर्घकालिक नजरिए के अनुरूप ही हैं।

स्पष्ट विकल्प | अगर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को अपनी इस लाइन पर संगठित करते हुए कथित बीजेपी समर्थक मन-मिजाज वाले नेताओं से मुक्त कर लेते हैं तो वोटरों के लिहाज से यह इस मायने में अच्छा होगा कि उनके सामने दोनों विकल्प पूरी तरह स्पष्ट होंगे। वे चाहें तो भारतीयता को लेकर संघ की दृष्टि को चुनें या कांग्रेस के नजरिए से सहमति दिखाएं या बारी-बारी दोनों को आजमाते रहें। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक के भ्रम में दूसरे को चुन लें और छला हुआ महसूस करें।

सबसे बड़ी परीक्षा | बहरहाल, एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस को हर चुनाव का सामना करना है। ऐसे में उसका नेतृत्व चाहे या न चाहे उसके हर कदम, हर फैसले को चुनावी कसौटी से गुजरना ही होगा। राहुल गांधी के ताजा बयान की भी सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि दो साल बाद होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में वह पार्टी के लिए कितना फायदेमंद या नुकसानदेह साबित होता है।

चक्र-व्यू

उम्र रिटायरमेंट की

राहुल पाण्डेय

अपने यहां कुछेक पेशे ऐसे हैं, जिनमें कभी रिटायरमेंट नहीं होती। पुलिस वाले कितनी भी लाठी फटकार लें, रिक्शे के कितने ही टायर पंक्चर कर लें, एक दिन आता है, जब वे रिटायर हो जाते हैं। अदालत में जज साहब कितनी भी जमानतें रद्द कर लें, उनकी रिटायरमेंट कभी रद्द नहीं होती है। मगर एक वकील मरते दम तक वकील रहता है। ऐसे ही एक डॉक्टर जब तक कागज पर ना समझी जाने वाली भाषा लिख लेता है, कभी भी रिटायर नहीं हो सकता। नेतागीरी भी एक ऐसा ही पेशा है, जिसमें लोग रिटायर नहीं होते। पड़ोसी मुल्क चीन में तानाशाही है, मगर वहां के नेता एक उम्र के बाद खुद ही निकल जाते हैं। लेकिन अपने यहां के नेताओं की उम्र का गणित ही दूसरा होता है।

अपने यहां राजनीति में कोई बूढ़ा नहीं होता। हम आप जब साठ पार होते हैं तो किसी के घुटने दर्द करते हैं, किसी की याददाश्त कम हो जाती है, किसी की आंखें कमजोर हो जाती हैं। मगर नेता जी के घुटने खराब होते हैं तो वे जमीन से ज्यादा जुड़ जाते हैं। आंखें कमजोर होती हैं तो भविष्यद्रष्टा बन जाते हैं। याददाश्त कमजोर होती है तो कहते हैं, अब पुरानी गलतियां कभी नहीं दोहराई जाएंगी। 60 से 80 साल वाले नेता युवा हृदय सम्राट होते हैं तो इसके पार वाले राजनीति के किशोर। हर चुनाव के बाद जनता को लगता है कि चलो, अब ये बूढ़े नेता हटेंगे, नई पीढ़ी आएगी। मगर जनता यह भूल जाती है कि भारतीय राजनीति में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अमेरिका में भी बाइडन उम्रदराज थे, याददाश्त धोखा देने लगी थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पीछे वह तभी हटे, जब उन पर अपनी ही पार्टी की ओर से दबाव बढ़ा। यह और बात है कि उनकी जगह जो प्रत्याशी आईं, वह भी ट्रंप के सामने नहीं टिक पाईं। अमेरिका में कोई व्यक्ति दो टर्म ही राष्ट्रपति रह सकता है। खैर, स्कॉटलैंड और न्यूजीलैंड की दो शीर्ष नेताओं ने हाल के वर्षों में राजनीति से शिखर पर रहते ही संन्यास ले लिया था। क्या भारतीय नेता भी उनसे कुछ सीखेंगे?

एकदा

स्टूडियो से नाता

बात 1937 की है। मुंबई में दादर स्टेशन के पूरब में दादा साहब फाल्के रोड पर मीठावाला चॉल है। इसके ठीक सामने है रूपतारा स्टूडियो। 4 साल की एक बच्ची स्टूडियो में आती-जाती गाड़ियों को देखती तो उसे भी अंदर जाने की इच्छा होती। एक दिन जब वह स्टूडियो के अंदर जाने लगी, तभी बड़ी-बड़ी मूछों वाले गार्ड ने उसे गेट से लौटा दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पास से गरमागरम पकौड़े खरीदकर मूंछ वाले पठान के पास गई।

पठान ने पकौड़े खाए, उसे गोद में उठाया और स्टूडियो में ले गया। अब अक्सर खेलते हुए वह गेट के पास आती, गार्ड मुंह घुमा लेता और वह अंदर चली जाती। अंदर वह घूमती-फिरती, शूटिंग देखती। उसके पिता भी गायन और वादन के लिए जब जाते, तो उसे साथ ले जाते। स्कूल की जगह स्टूडियो और शो में जाने वाली इस बच्ची पर एक दिन डायरेक्टर विजय भट्ट की नजर पड़ी। उन्हें 'लेदरफेस' फिल्म के लिए 4 साल की बच्ची की जरूरत थी। उन्होंने उसी बच्ची को ले लिया। इस काम के लिए उसे 25 रुपये मिले। उस समय तीन पैसे किलो चीनी और तीन रुपये में ऊनी सूट बनता था। महजबीं बानो नाम की उस लड़की में अभिनय कला का जन्म इस तरह स्टूडियो में हुआ। यही बच्ची आगे चलकर मीना कुमारी के नाम से मशहूर हुई। 1960 में एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया, ' चार साल की उम्र में माता-पिता का सहारा बनने पर मुझे गर्व है। दिल से किया गया काम मनुष्य को शिखर तक ले जाता है।'

संकलन : हरिप्रसाद राय

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शादी के रिश्ते में महिलाओं के आर्थिक हितों को मिली अतिरिक्त सुरक्षा

शादी अमान्य हो तो भी गुजारा भत्ता मान्य?

राजेश चौधरी

शादी अमान्य करार हो जाए तो भी गुजारा भत्ता देने से पार्टनर बच नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में यह फैसला दिया है। इस फैसले का असर दूरगामी होगा क्योंकि वैवाहिक विवाद में कई बार पक्षकार यह साबित करने में लगे रहते हैं कि वे शादीशुदा जोड़ा नहीं हैं। हालांकि यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि अगर कोई कपल पति-पत्नी की तरह रहता है तो यह धारणा होगी कि वह शादीशुदा जोड़ा है। हाल के कानूनी बदलाव और शीर्ष अदालत के फैसलों ने महिलाओं को ऐसे मामलों में प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है।

शीर्ष अदालत ने क्या कहा | सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 11 के तहत अगर किसी विवाह को अमान्य घोषित कर दिया जाता है, तो भी पीड़ित पक्ष इस एक्ट की धारा 25 के तहत स्थायी भरण-पोषण या गुजारा भत्ता मांग सकता है। उसे राहत मिलेगी या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा। इसमें मामले की परिस्थितियों और पक्षकारों के आचरण को ध्यान में रखा जाएगा। अंतरिम भरण-पोषण का अधिकार धारा-24 के तहत है।

पति का तर्क खारिज | अगर अदालत प्रारंभिक रूप से किसी विवाह को अमान्य मानती है, तो भी मुकदमे के अंतिम निर्णय तक, धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण दिया जा सकता है। अदालत ने याची पति के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि यदि विवाह अमान्य है, तो स्थायी भरण-पोषण की मांग नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 25(1) को पढ़ते समय तलाक की डिक्री और विवाह अमान्यता की डिक्री में कोई अंतर नहीं किया गया है, इसलिए धारा 11 के तहत अमान्य विवाह के मामलों में भी गुजारा भत्ता मांगा जा सकता है।

आर्थिक-शारीरिक सुरक्षा | वैसे पहले से तय व्यवस्था के मुताबिक, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट के तहत अपने पार्टनर से गुजारा भत्ता पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।

कानून की गुत्थी

- शादी अमान्य तो भी गुजारे भत्ते का हक
- बरसों तक साथ रहे तो माने जाते हैं कपल
- शादी की मंशा न हो तो संबंध बनाना अपराध

Istock

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि लिव इन में रह चुकी महिला अपने पार्टनर के खिलाफ कानूनी रास्ता अख्तियार कर सकती है और डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट के तहत गुजारा भत्ता पाने की भी हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अगर यह मान भी लिया जाए कि महिला शादीशुदा नहीं है तो डीवी एक्ट के तहत महिला गुजारा भत्ता की हकदार हो सकती है।

रेप ना हो, अपराध तो है | पिछले साल सरकार ने क्रिमिनल लॉ में बदलाव किया है। उसमें शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने को रेप के दायरे से बाहर कर दिया गया। लेकिन इसे अलग से अपराध की श्रेणी में अभी भी रखा गया है। यानी महिला के साथ शादी का अपना वादा पूरा करने की मंशा न रखते हुए भी अगर कोई संबंध बनाता है तो यह रेप भले न हो, अपराध जरूर है। इसके लिए 10 साल तक कैद की सजा हो सकती है। यानी कपल के बीच संबंध बने और ब्रेकअप हुआ और संबंध की बुनियाद शादी का वादा है तो आपराधिक मुकदमा कायम होगा। दूसरे शब्दों में, कोई जोड़ा शादी के रिलेशन में हो या लिव इन में हो या फिर शादी अमान्य हो गई हो, अलगाव की स्थिति में महिला को आर्थिक तौर पर पूरी सुरक्षा मिलेगी।

शादीशुदा कपल की धारणा | दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि अगर कपल पति-पत्नी की तरह सालों से साथ रह रहे हैं तो ये माना जाएगा कि दोनों शादीशुदा हैं। ऐसे में महिला पत्नी की तरह गुजारा भत्ता मांग सकती है। दरअसल, इस मामले में पुरुष ने हाईकोर्ट में दावा किया था कि महिला उसकी पत्नी नहीं है। हालांकि कपल पति-पत्नी की तरह 20 साल साथ रहे थे और तमाम साक्ष्यों के आधार पर फैमिली कोर्ट ने दोनों को पति-पत्नी माना था। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में व्यवस्था दे रखी है कि अगर कोई कपल लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं तो सीआरपीसी की धारा-125 के तहत गुजारा भत्ता का दावा करते समय शादी के सबूत पेश करने की शर्त नहीं रखी जा सकती। कपल पति-पत्नी के तौर पर लंबे समय से साथ रहते हैं तो यह धारणा होती है कि दोनों शादीशुदा कपल हैं और इस आधार पर सीआरपीसी की धारा-125 के तहत महिला गुजारा भत्ता पाने के लिए दावा कर सकती है।

एक कदम आगे | मद्रास हाईकोर्ट हो या दिल्ली हाईकोर्ट ऐसे तमाम मामले सामने आते रहे हैं जिनमें पति का कहना होता है कि चूंकि शादी का कोई सबूत नहीं है इसलिए उसे गुजारा भत्ता देने को मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि ऐसे मामलों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि अगर आदमी और औरत लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहे हैं तो गुजारा भत्ता के दावे के मामले में दोनों धारणा के तहत पति-पत्नी माने जाएंगे। दरअसल, कानून और सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को हर स्थिति में प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। इससे महिलाएं पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर ज्यादा सुरक्षित महसूस कर पाएंगी।

Tech की भाषा बने तो होगी संस्कृत की प्रगति

शैलेंद्र पांडेय

अंग्रेजी में कहावत है, 'Put someone on a pedestal' यानी किसी को बहुत ऊंचा उठा देना। लेकिन, इससे कई बार वास्तविकता और कल्पना के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है। यह तरीका किसी को पूजनीय तो बना सकता है, लेकिन समाज से भी दूर कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ है संस्कृत के साथ। हमारे आदर और सम्मान ने इसे देववाणी बना दिया, पर आम जन से काट दिया। यह ऐसी भाषा बन कर रह गई, जो अब सुनाई पड़ती है धार्मिक आयोजनों में और जिसे पढ़ने-बोलने के लिए भी 'पंडित' चाहिए।

आंदोलन चाहिए | सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक भाषाओं में से एक संस्कृत अरसे से इसी संकट से जूझ रही है। इससे निकल कर कई भारतीय भाषाएं विकसित हुईं और अपनी अलग राह पकड़ ली, पर संस्कृत लगता है कि वहीं ठहर कर रह गई। इसके पास सम्मान तो है, मगर स्वीकार्यता नहीं। आदर है, अपनापन नहीं। आज संस्कृत को कुछ उसी तरह के आंदोलन की जरूरत है, जैसा कभी हिब्रू के लिए हुआ था।

हिब्रू से सीख | हिब्रू भी कभी बस देववाणी ही थी, धार्मिक ग्रंथों और यहूदी प्रार्थनाओं तक सीमित। 19वीं सदी के आखिर में फिर इसका पुनर्जन्म होता है और इसका श्रेय दिया जाता है Eliezer Ben-Yehuda को। येहूदा ने हिब्रू को आम लोगों की भाषा बनाने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने इसका पहला आधुनिक शब्दकोश तैयार किया, जिसमें नए शब्द गढ़े गए और पुराने शब्दों को समकालीन संदर्भ में इस्तेमाल किया गया। हिब्रू में पहला अखबार निकाला।

सरकारी प्रयास | येहूदा ने हिब्रू बाइबिल की भाषा को आम लोगों के बीच ला खड़ा किया। यह सामाजिक प्रयास बाद में इस्राइल के गठन के साथ सरकारी बन गया। आज यह इस्राइल की आधिकारिक भाषा है और लगभग पूरी आबादी की पहली जुबान।

समझने में भूल | वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग के प्रफेसर हरि प्रसाद अधिकारी मानते हैं कि संस्कृत को समझने में चूक हो गई। इसमें धर्म, दर्शन, विज्ञान से जुड़ी ऐसी बातें हैं, जो आज भी दुनिया के लिए प्रासंगिक बनी हुई हैं। लेकिन, लोग यह भूल गए और कर्मकांड हावी हो गए।

AI Image

कॉमन रूम

प्राचीन ज्ञान का खजाना | वेद, उपनिषद से लेकर गीता के उपदेश तक - भारत का सारा प्राचीन ज्ञान संस्कृत में है। मनीषियों ने संस्कृत को चुना, क्योंकि वही आम जन की भाषा थी। और यह भी तथ्य है कि जो संस्कृत में लिखा, वही आज भी बचा है। केवल वैदिक या सनातन ही नहीं, बौद्ध और जैन धर्मों ने भी संस्कृत का सहारा लिया।

प्रयास जारी | अब संस्कृत किस तरह पुराने स्वरूप को पा सकती है? प्रफेसर अधिकारी बताते हैं कि लोकभाषा प्रसार समिति और संस्कृत भारती संघ जैसे संगठन इस दिशा में काम कर रहे हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत भी रिसर्च की जा रही है। हालांकि इसके साथ ही जरूरत है संस्कृत को इनोवेशन और टेक्नॉलजी से जोड़ने की।

AI में संस्कृत | चीनी, फ्रेंच या जर्मन अब AI की भाषा बन चुकी हैं। चैटबॉट्स, टेक्स्ट और इमेज जेनरेशन, स्पीच रिकग्निशन में इनका इस्तेमाल होता है। संस्कृत को भी उसके खांचे से निकाल कर यहां तक लाने की जरूरत है। इसमें हमें नए शब्द, नए मुहावरे चाहिए ताकि यह समकालीन भाषा बन सके। जिस दिन सर्च और चैटिंग में संस्कृत आम हो जाएगी, उस दिन यह आम बन जाएगी।

पशिचम की कंपनियों का गोरखधंधा

विचार विंडो

मृत्युंजय राय

ZERO SUM: The Arc of International Business in Russia में चार्ल्स हेकर (Charles Hecker) सोवियत संघ के टूटने के बाद से लेकर कुछ महीने पहले तक यहां विदेशी कंपनियों के कामकाज के बारे में लिखते हैं। इस अवधि में अंतरराष्ट्रीय बिजनेस के साथ क्या हुआ, इसे मैकडॉनल्ड्स की मिसाल से समझा जा सकता है। 1990 की जनवरी में मॉस्को में मैकडॉनल्ड्स का पहला स्टोर खुला। तब रेस्तरां में काम करने के लिए हजारों लोगों ने अर्जियां दीं और हजारों 'बिग मैक' के जायके के लिए घंटों लाइन में इंतजार करते रहे। चार्ल्स लिखते हैं कि पुश्किन स्क्वेयर पर यह रेस्तरां आज भी है, लेकिन 2022 में (यूक्रेन युद्ध के बाद विदेशी कंपनियों के देश छोड़ने की वजह से) इसका मालिकाना हक स्थानीय हाथों में आ गया और मैकडॉनल्ड्स की जगह नाम रूसी हो गया, जिसका मतलब हिंदी में 'स्वादिष्ट' है।

AI Image

मैकडॉनल्ड्स ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भले ही यहां से कारोबार समेट लिया, लेकिन कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां पश्चिम देशों के आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बाद भी यहां कारोबार कर रही हैं। चार्ल्स तो यह भी लिखते हैं कि इन कंपनियों ने पिछले तीन साल में रूस की सरकार को कोई 16 बिलियन डॉलर का टैक्स दिया है।

चार्ल्स पहले मॉस्को टाइम्स के रिपोर्टर के रूप में और बाद में जियोपॉलिटिकल रिस्क कंसल्टेंट के तौर पर अमेरिकी-यूरोपीय कंपनियों को रूस में निवेश सलाहकार की भूमिका में उन्होंने यहां अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के कारोबार को करीब से देखा है। 1990 के दशक के मध्य में वह अमेरिका से रूस पहुंचे थे। कम्युनिस्ट शासन के खत्म होने के बाद हजारों की संख्या में अंतरराष्ट्रीय कंपनियां तब रूस में दाखिल हुईं। चार्ल्स लिखते हैं कि इससे रियल एस्टेट की मांग इतनी बढ़ गई कि एक वक्त ऐसा आया जब मॉस्को में प्रॉपर्टी की कीमत न्यूयॉर्क सिटी से अधिक हो गई। इस दौरान घरेलू कंपनियों ने भी तरक्की की। 2014 में जब रूस ने क्राइमिया को यूक्रेन से छीन लिया, तब रूस का निर्यात 600 बिलियन डॉलर पहुंच गया था, जो कि 1999 में व्लादिमीर पूतिन के सत्ता संभालने के वक्त 100 बिलियन डॉलर था।

चार्ल्स लिखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने इस दौरान खुद को रूसी तौर-तरीकों के हिसाब से बदला भी। यानी इलीगल कैश ट्रांजेक्शन, सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देना, कुछेक को छोड़कर बाकी पश्चिमी कंपनियां ये सब कर रही थीं। वह लिखते हैं कि पश्चिम की नजर तब सिर्फ रूस से मुनाफा बटोरने पर थी। 2008 में जॉर्जिया पर हमले और 2014 में क्राइमिया पर कब्जे के बाद भी पश्चिमी कंपनियां रूस में कारोबार करती रहीं। पश्चिम को इस दौरान यही लगता रहा कि समय, पैसा और प्रोत्साहन की वजह से रूस आगे चलकर उदार लोकतंत्र में बदल जाएगा। आज जब डॉनल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की पर दबाव डाल रहे हैं तो इससे पूतिन जरूर खुश होंगे।

शादी से पहले संवाद

आधी दुनिया

प्रणव प्रियदर्शी

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इस बार राष्ट्रीय महिला आयोग की एक अनूठी पहल खासी चर्चित हो रही है। आयोग की ओर से देश भर में 21 विवाह-पूर्व संवाद केंद्र गठित किए गए। यह पहल इस अर्थ में अनूठी है कि इसमें शादी होने और फिर कपल में मतभेद बढ़ने के बाद उन्हें दूर करने का नजरिया न रखते हुए इस मसले को ज्यादा प्रो-एक्टिव ढंग से देखने की कोशिश की गई है। आज के दौर में पुरुष-स्त्री संबंधों के व्याकरण पूरी तरह बदलते दिख रहे हैं। लड़कियां पढ़ाई और करियर में जैसे-जैसे आगे बढ़ रही हैं, खुद को और अपने आसपास की दुनिया को देखने के उनके नजरिए में बदलाव आ रहा है। परिवार, समाज और शादी को लेकर भी उनकी दृष्टि बदल रही है। यही चीज दूसरी तरफ से भी हो रही है। यानी परिवार, समाज और पुरुषों के लड़कियों को देखने के नजरिए में भी इससे बदलाव आ रहा है। इसका नतीजा अक्सर नजरिये के टकराव के रूप में सामने आता है। स्वाभाविक ही शादियों में भी इस तरह के टकराव बढ़े हैं। यह स्थिति युवाओं के एक हिस्से में शादी को लेकर अरुचि या आशंका पैदा कर रही है। लिव-इन के बढ़ते चलन को भी अक्सर इससे जोड़कर देखा जाता है। ऐसे हालात में राष्ट्रीय महिला आयोग की यह पहल सराहनीय है। इन केंद्रों में प्रफेशनल काउंसलर होंगे जिनकी काउंसलिंग शादी से पहले कपल में एक-दूसरे के नजरिये को समझने और असहमतियों का सम्मान करने की भावना विकसित करने में मददगार हो सकती है। हालांकि यह पहल अभी लॉन्च ही हुई है। देखना होगा कि व्यवहार में इसे कैसे आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि यह एक सामयिक पहल है जिस पर सही ढंग से अमल कई जिंदगियों को बिगड़ने से बचा सकता है।

AI Image

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

मन का स्वभाव है भटकना, उसे सहारा दीजिए

श्री श्री आनंदमूर्ति

मन का स्वभाव ऐसा है कि वह किसी चीज से जुड़े बिना रह नहीं सकता। जब तक उसका ध्यान किसी चीज पर केंद्रित न हो, भटकता रहता है। इसलिए क्यों न इसे केवल एक ही चीज पर केंद्रित किया जाए, और वह हो परम सत्ता। लेकिन, सिर्फ किसी चीज से जुड़ना ही काफी नहीं है, मन को स्थिर करना भी जरूरी है। जब मन पूरी तरह से केंद्रित होता है, तभी परम सत्ता से मिल सकता है।

मन को केंद्रित करने का सबसे सरल तरीका है जप करना। जप का अर्थ है किसी शब्द या मंत्र को बार-बार दोहराना। जब कोई शब्द या नाम दोहराना ही है, तो क्यों न परम सत्ता के नाम का जप किया जाए। जप तीन प्रकार का होता है। मानसिक जप में मन ही मन मंत्र दोहराते हैं और इसे केवल हम ही सुन सकते हैं। यह जप का सबसे उच्च स्तर है। उपांशु जप में होंठ हिलते हैं, लेकिन ध्वनि नहीं निकलती और केवल हम ही इसे सुन सकते हैं। वाचनिक जप में हम अपनी आवाज से मंत्र का उच्चारण करते हैं। यह जप का सबसे साधारण रूप है।

इन तीनों में मानसिक जप सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें मन पूरी तरह से परम सत्ता पर केंद्रित रहता है। जब हम जप करते हैं, तो सिर्फ नाम नहीं दोहराते, बल्कि उस सर्वोच्च सत्ता की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। इस समर्पण को ही नमः कहा जाता है। यानी, जब हम किसी को नमः कहते हैं, तो उसकी सर्वोच्चता स्वीकार कर रहे होते हैं। इसलिए, परम सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखना चाहिए।

इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ गतिशील है। इसलिए इसे जगत कहा जाता है, जिसका अर्थ ही होता है जो निरंतर गति में है। लेकिन, इस निरंतर परिवर्तनशील संसार में कोई तो ऐसा बिंदु होना चाहिए, जहां सब कुछ जाकर रुक जाए। कोई ऐसा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, जहां सारी गतिविधियां समाप्त होती हैं। और हर मनुष्य ऐसी जगह पहुंचना चाहता है, जहां उसे ऐसा विराम मिल जाए। यही अंतिम लक्ष्य परम पुरुष है। वही एकमात्र सत्ता है जो किसी अन्य चीज पर निर्भर नहीं करती। वही भवसागर पार कराते हैं।

अगर किसी विशाल समुद्र को पार करना हो, तो क्या आप तैरकर पार करेंगे? यह संभव नहीं है। लेकिन, अगर आपके पास एक अच्छी नाव हो, तो आप आराम से इसे पार कर सकते हैं। यही परम सत्ता है- एक नाव, जो हमें इस भवसागर से पार कर सकती है। अगर जीवन में शांति और स्थिरता चाहिए, तो परम सत्ता की शरण में जाना ही सबसे अच्छा तरीका है।

प्रस्तुति : दिव्यचेतनानंद अवधूत

[illegible]

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

बेटियों के लिए नई राह

8 मार्च का लेख 'बेटे कब बेटियों की तरह बड़े होंगे' पढ़ा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम दुनिया भर की महिलाओं के जुनून को सलाम करते हैं। महिलाओं ने शिक्षा और नौकरियों में सफलता पाने के लिए ऐतिहासिक चुनौतियों और समस्याओं को पार किया है। फिर भी उन्हें समान रूप से सम्मान नहीं मिल पाता है। क्या महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली नीतियां प्रभावी ढंग से लागू की जाएंगी? इस पर सोचेंगी कि श्रम शक्ति में समान समावेश कैसे हो सकता है और सार्वजनिक स्थानों पर भय से मुक्ति कैसे मिल सकती है? ये ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना होगा। देश की बेटियों के लिए नई राह बनानी होगी।

अंशु भारती, ईमेल से

विकल्प तलाशे भारत

यह पत्र 7 मार्च के संपादकीय 'भारत करे सौदेबाजी' से संबंधित है। मेरा मानना है कि मौजूदा हालात इस बात का संकेत दे रहे हैं कि भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ट्रंप देश की तिजोरी भरने में लगे हुए हैं। इसलिए भारत को चाहिए कि विश्व के जो देश डॉनल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का शिकार हैं, उनसे संबंध बनाकर अपना सारा ध्यान उन देशों से व्यापार करने पर केंद्रित करे- जैसे कनाडा और मैक्सिको।

वारिस अली खान, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

चीन की भारत को दोस्ती की पेशकश – एक खबर

– ट्रंप के टैरिफ से कहीं चीन मजबूर ते नहीं हुआ!

तुषार मिस्त्री

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 19

प्रकटीकरण और नियमन

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के नए अध्यक्ष तुहिन कांत पांडेय ने गत सप्ताह पद संभालने के बाद पहली सार्वजनिक उपस्थिति में कुछ उत्साहवर्धक टिप्पणियां की हैं। बाजार में पारदर्शिता पर जोर देते हुए पांडेय ने कहा कि यह नियामक पर भी लागू होती है। उन्होंने कहा कि नियामक को विभिन्न मोर्चों पर पारदर्शी होने की आवश्यकता है। इसमें बोर्ड में हितों का टकराव भी शामिल है। दिलचस्प बात है कि यह हिस्सा नियामक की वेबसाइट पर अपलोड किए गए भाषण में शामिल नहीं है। हालांकि टिप्पणी उनके लिए तैयार किए गए भाषण का हिस्सा थी या नहीं लेकिन अब उनके विचार सार्वजनिक मंच पर हैं और सभी को उनका स्वागत करना चाहिए। सेबी को भी जल्द से जल्द इसका पालन शुरू करना चाहिए।

प्रकटीकरण संबंधी टिप्पणियों को पांडेय की पूर्ववर्ती सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च जो अब बंद हो चुकी है, उसने बुच पर अदाणी समूह पर चल रही जांच को लेकर हितों के टकराव का इल्जाम लगाया था। हिंडनबर्ग ने पहले भी अदाणी समूह पर कई इल्जाम लगाए थे। इसकी प्रतिक्रिया में बुच और नियामक दोनों ने वक्तव्य जारी किए। तब सेबी ने कहा कि उसके यहां प्रकटीकरण की ठोस व्यवस्था है। आरोपों की प्रकृति को देखते हुए (इस समाचार पत्र सहित) यह कहा गया कि सेबी को बेहतर मानक अपनाने चाहिए। उदाहरण के लिए अगस्त 2024 के संपादकीय में कहा गया था, 'प्रमुख लोगों के प्रकटीकरण मानकों को मजबूती देने तथा भविष्य में किसी अटकल को समाप्त करने के लिए नियामक को ऐसे लोगों के वित्तीय हितों को सार्वजनिक करना चाहिए।' आधुनिक वित्तीय बाजारों में जहां वित्तीय समेत तमाम फंड बहुत आसानी से आ और जा सकते हैं, विनियमित संस्थाओं और नियामक संस्था के प्रमुख लोगों के लिए सभी प्रासंगिक प्रकटीकरण होना चाहिए। इससे व्यवस्था में विश्वास मजबूत होगा।

प्रकटीकरण के विषय से अलग पांडेय ने कुछ अन्य अहम बातें भी कहीं जिनका उल्लेख जरूरी है। नियामक अधिकतम नियमन की ओर देखेगा। अगर कुछ कानून ऐसे हो गए हैं जो कोई उद्देश्य पूरा नहीं कर रहे हैं तो नियामक उनकी समीक्षा को लेकर खुला रुख रखेगा। यह सकारात्मक वक्तव्य है और सरकार की समग्र विचार प्रक्रिया के अनुरूप भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक विनियमन आयोग के विचार का जिक्र किया ताकि पुराने कानूनों और नियमन से निजात पाई जा सके। सेबी आंतरिक तौर पर बहुत कुछ कर सकता है जो नियमित संस्थानों के लिए हालात सामान्य बनाएगा। इस मोर्चे पर प्रतिभूति बाजार नियामक ऐसे नियमन को अपनाने पर काम कर रहा है जहां उभरती बाजार परिस्थितियों का ध्यान रखा जा सके। उदाहरण के लिए ऐसे बदलावों ने नए जमाने की तकनीकी कंपनियों को भारतीय शेयर बाजार से पूंजी जुटाने का अवसर दिया है। नियमन में निरंतर सुधार से भारतीय बाजार पूंजी जुटाने और सूचीबद्धता के लिहाज से बेहतर बनेगा। मौजूदा वित्त वर्ष में जनवरी तक, कंपनियों ने रिकॉर्ड 4 लाख करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी जुटाई जो 2023-24 में जुटाई गई कुल पूंजी से दोगुनी है। बीते वर्षों के दौरान सेबी ने भी म्युचुअल फंड्स की पहुंच बढ़ाने में भी मदद की है जिसने देश के पूंजी बाजारों को गहन बनाया है।

सेबी के चेयरमैन ने यह भी कहा कि नियामक विदेशी पूंजी जुटाने के लिए अनुकूल माहौल बनाने को लेकर सचेत है और वह अंशधारकों के साथ संवाद का इच्छुक है। यह भी एक स्वस्थ संकेत है। अगर भारत को निरंतर टिकाऊ रूप से उच्च वृद्धि हासिल करनी है तो यह अहम होगा कि पूंजी बाजार सुचारु रूप से काम करें और बचत को न्यूनतम समस्या के साथ निवेश में ला सकें। हालांकि सेबी इस दिशा में काम कर रहा है लेकिन समय आ गया है कि प्रक्रियाओं को और सुसंगत बनाकर भारतीय पूंजी बाजार और अर्थव्यवस्था के लिए संभावनाओं को बेहतर बनाया जा सके।

बोफोर्स तथा राजीव काल के बहाने स्थिति का आकलन

बोफोर्स तथा अन्य बातों के लिए राजीव गांधी को कोसने का चलन बन गया है मगर सच यह है कि 1985 से 1989 तक वह इकलौता दौर था, जब हमारे देश ने भविष्य को ध्यान में रखकर हथियार खरीदे थे

राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

सबसे पहले वादा कीजिए कि आप लेख का आखिरी हिस्सा पहले नहीं पढ़ेंगे। इस लेख में एक होशियारी की गई है, जो आखिर में सामने आएगी। अरसे बाद भारत को ऐसा सैन्य प्रमुख मिला है जो कटु सत्य बोल रहा है। एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह लगातार कहते आए हैं कि भारत की वायु सेना और प्रतिद्वंद्वी देशों की वायु सेना में कर्मचारियों तथा तकनीक के मामले में बहुत अंतर है। रक्षा क्षेत्र में जहां सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) का एकाधिकार है वहां सारे सवालों से परे मानी जाने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को भी उन्होंने आईना दिखा दिया। इस कंपनी को उन्होंने कैमरे और माइक्रोफोन के मामले में आड़े हाथों लिया। उनका बयान एकदम अलग लगता है क्योंकि हमें अपने सैन्य प्रमुखों से दीन-हीन अंदाज में यही सुनने के आदी हो गए हैं, '...हमारे पास जो है हम उसी से लड़ लेंगे।'

वायु सेना प्रमुख ने जो चुप्पी तोड़ी है उस पर प्रतिक्रियाएं उम्मीद के मुताबिक ही आ रही हैं। जब भी कोई कहता है कि सशस्त्र बलों के पास हथियारों की कमी है तो उसके बारे में यही कहा जाता है कि वह बिका हुआ है, या आयात का हिमायती है। आरोप लगाया जाता है कि दुष्टों की मंडली भारत को खुद की क्षमता तैयार करने से रोक रही है और महंगे आयात पर निर्भर रखना चाहती है। रक्षा क्षेत्र भी 'इन्फ्लुएंसर्स' का मैदान बन गया है और सेनाओं के प्रमुख सावधान हो गए हैं। इस बीच डॉनल्ड ट्रंप ने आग में एफ-35 का घी डाल दिया है।

इन बातों ने रक्षा खरीद को लगभग असंभव बना दिया है। भारत में अब भी बहुत कम हथियार और उपकरण बनते हैं। जो बनते हैं वे भी साझे उपक्रमों में बनते हैं। जब बढ़ते स्वदेशीकरण की डींगें हांकी जाएं तब खुद से पूछिए कि 200 से अधिक सुखोई 30-एमकेआई और असंख्य जगुआर या मिग बनाने के बाद भी क्या हम एक पूरा विमान अपने दम पर तैयार कर सकते हैं? हम चीनियों की तरह ऐसा नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि हमने 36 राफेल विमानों की खरीद को साहसी कदम बताया था। इससे गतिरोध टूटा और नई दिल्ली में चल रही लॉबीइंग और लीक बनाम लीक के सिलसिले को चुनौती मिली। परंतु हमने इसके विरुद्ध आने वाला तर्क भी स्वीकार किया: आखिर भारत के लिए ऐसी नौबत ही क्यों आई? नतीजा रहा पांच अरब डॉलर की खरीद मानो जंग के दौरान हड़बड़ी में कुछ खरीदा जा रहा हो। अपने ऊपर 'हथियारों के सबसे बड़े आयातक' का शर्मनाक ठप्पा हमने खुद लगाया है।

स्टॉकहोम की संस्था सिपरी जो डॉलर की 1990 की कीमत पर आयात का हिसाब लगाती है। उसके हिसाब से 2015 से 2024 के बीच 10 सालों में भारत का कुल हथियार आयात 23.7 अरब डॉलर से थोड़ा अधिक रहा। यह वैश्विक हथियार आयात का 9.8 फीसदी है मगर औसतन 2.3 अरब डॉलर के ही हथियार हर साल खरीदे गए।

यहां दो बातें हैं। पहली बात, नरेंद्र मोदी का राफेल, अपाचे, एम-777 माउंटेन हविट्जर, हारपून मिसाइल, एमएच-60 रोमियो नौसैनिक हेलीकॉप्टर, और एमक्यू-9बी ड्रोन आदि की सीधी खरीद का फैसला वैसा ही बहादुरी और समझदारी भरा फैसला था जैसे कोई अनुभवी डॉक्टर मरीज की बिगड़ती हालत देखकर एक के बाद एक सर्जरी करता जाता है। दूसरा एक प्रश्न है। दो सीमाओं पर लगातार और सीधे जूझने वाली दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना खुद को हमेशा आईसीयू में यानी ऐसी तंगी में कैसे रख सकती है कि अक्सर उसकी आपातकालीन सर्जरी करनी पड़े।

आप पलटकर मुझसे भी सवाल कर सकते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक हथियार आयात करने वाला देश पर खरीद से डरने की तोहमत कैसे लगा सकते हैं? फिर उसके पास हमेशा जरूरी हथियारों की कमी क्यों रहती है? ये जायज सवाल हैं और भारत की रक्षा योजना के विरोधाभासों को सामने रखते हैं। इस पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं। मेरी पसंदीदा किताब है स्वर्गीय स्टीफन पी कोहेन और सुनील दासगुप्ता की पुस्तक 'आर्मिंग विदआउट एमिंग', जो भारत में सामरिक सोच और योजना की संस्कृति न होने पर अफसोस जताती है।

इसमें लेखक बताते हैं कि भारत का सिद्धांत पूरी तरह फौरी जरूरतें पूरी करने वाला है। इस बारे में मेरा नजरिया मेरे व्यक्तिगत दस्तावेजों पर आधारित है। मेरे पास एक नोट है, जो आगे चलकर देश के रक्षा मंत्री बने जसवंत सिंह ने पेंसिल से कागज के एक पुर्जे पर लिख दिया था। 1994 की गर्मी में साल्जबर्ग में सामरिक मामलों पर एक कार्यक्रम के दौरान जब जनरल सुंदरजी भारत के सामरिक सिद्धांत की कमजोरियां गिना रहे थे तब सिंह ने मुस्कराते हुए यह पुर्जा मुझे थमाया था। उन्होंने लिखा था, 'भारत के सैन्य-रणनीतिक सिद्धांत की पड़ताल के लिए बनी संसदीय समिति का अध्यक्ष मैं ही था। हमने देखा कि न तो कोई रणनीति है और न ही कोई सिद्धांत।'

इसमें बदलाव आने का कोई सबूत नहीं मिलता क्योंकि अगर बदलाव आया होता तो हम मोर्चे पर जाने वाले लड़ाकू विमान ऐसे नहीं खरीद रहे होते जैसे सुपरमार्केट से राशन खरीद रहे हों या हैम्लीज से खिलौने खरीद रहे हों। या हम एक साथ सैकड़ों एंटी-टैंक मिसाइल या करीब 60,000 इन्फैंट्री राइफल नहीं खरीद रहे होते। हमारी रक्षा खरीद का यही इतिहास रहा है। बस 1985 से 1989 के बीच राजीव गांधी का दौर इससे अलग था मगर उसमें से बोफोर्स का वायरस निकल आया।

इसी वायरस के डर से खरीद न्यूनतम हो गई। वरना बालाकोट के बाद मिग-21 बाइसन को एफ-16 के बेड़े में क्यों शामिल कर दिया जाता? याद कीजिए करगिल में कैसे शुरुआत में भारतीय वायु सेना को झटके झेलने पड़े थे। उसे दो मिग विमान और एक एमआई-17 लड़ाकू हेलिकॉप्टर गंवाने पड़े थे और एक को छोड़कर उसमें सवार सभी लोग मारे गए थे। जो शख्स बच गया था उसे भी पाकिस्तान ने युद्धबंदी बना लिया था। चौथा शक्तिशाली टोही विमान कैनबरा था, जिसका इंजन फेल हो गया और जिसे कुशल चालक दल बचाकर वायुसेना अड्डे पर ले आया था। बाद में विमान को वायुसेना से हटा लिया गया। चारों विमानों और हेलिकॉप्टरों को कंधे पर रखी मिसाइल से दागा गया था। इसके बाद वायु सेना ने रातोरात अपने मिराज विमानों के लिए इजरायल से लेसर उपकरण खरीदे और तस्वीर एकदम बदल गई।

ये उदाहरण 'सब चलता है' वाले रुख की मिसाल देने के लिए नहीं है। हम इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश में हैं कि खरीद से डर क्यों लगता है? 1987 से इसकी एक वजह बोफोर्स का खौफ है। हर रक्षा खरीद में देर की जाती है, जॉर्ज फर्नांडीज के शब्दों में कहें तो उसे अनिर्णय की भूलभुलैया में फेंक दिया जाता है। यही वजह है कि भारत में हथियारों के सौदागरों, बिचौलियों और बी 2 बी हथियार बाजार के लिए जगह बन जाती है। जनता सौदेबाजी और बदलती जरूरतों के बीच भ्रमित है, जबकि हम किसी भी और देश से ज्यादा आयात कर रहे हैं। विरोधाभास देखेंगे? 1991 के बाद हुए रक्षा मंत्रियों में एके एंटनी को सबसे अधिक अमेरिका विरोधी और जोखिम से बचने वाला माना जाता है लेकिन अमेरिका से सबसे ज्यादा हथियार भी उन्होंने ही खरीदे। सी-130, सी-17 और पी-8आई की खरीद सरकारों के बीच सौदे से की गई और ऐसी की गई, जो आजादी के बाद कभी नहीं हुई थी। नरेंद्र मोदी ने थोड़ी ज्यादा जल्दबाजी के साथ वही तरीका फिर चलाना शुरू कर दिया।

डर से लड़ना है तो उसका सामना करना होगा। राजीव गांधी को बोफोर्स आदि के लिए कोसना आसान है मगर सच यह है कि 1985 से 1989 का दौर वह है, जब सबसे अधिक सक्रियता के साथ हथियार खरीदे गए और भविष्य का ध्यान रखा गया। आज भी तीनों सेनाओं द्वारा इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर उपकरण राजीव गांधी के समय खरीदे गए थे। उदाहरण के लिए मिराज, टी-72 टैंक, नई सीरीज के मिग, बीएमपी सशस्त्र लड़ाकू वाहन और बोफोर्स। उन सालों में हमारा रक्षा बजट भी जीडीपी के 4 फीसदी की लक्ष्मण रेखा लांघ गया था।

आंकड़े बताते हैं कि यह डर कितना नुकसानदेह है। पिछले दशक में हमारा रक्षा आयात सोने के सालाना आयात के आधे से भी कम रहा। सच कहें तो यह रिलायंस इंडस्ट्रीज के आयात पर होने वाले खर्च के 5 फीसदी से भी कम और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के आयात खर्च के करीब 8 फीसदी के बराबर रहा था। हम साल में औसतन 2.3 अरब डॉलर का सैन्य आयात करते हैं, जो हमारे उर्वरक आयात के एक चौथाई से भी कम है। किसानों के लिए खरीद में जवानों के लिए खरीद से कम घोटाले क्यों होते हैं? रक्षा आयात पर विवाद इसलिए नहीं होता कि इनका आकार बड़ा होता है। विवाद इसलिए होता है क्योंकि ये छोटे होते हैं, इसमें कई कंपनियां होती हैं और पूरे सिस्टम में डर बैठा हुआ है। अगर हम इस डर पर जीत हासिल नहीं करते तो हम खुद को हमेशा मुश्किल में पाएंगे और जल्दबाजी में खरीद करनी होगी।

अब आखिर में बताता हूं कि मैंने क्या होशियारी की थी। मैंने अप्रैल 2015 में राफेल विवाद के बाद एक लेख लिखा था। इस हफ्ते का आलेख बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़े आंकड़े और संदर्भ बदले हैं। इससे पता चलता है कि हालात बदलना या नहीं बदलना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति का उतना ही बड़ा मखौल है।

स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ें सुनियोजित कदम

जमीनी हकीकत
सुनीता नारायण

हमारी दुनिया बदल चुकी है और इस बारे में किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। जलवायु के जोखिम भरा यह डॉनल्ड ट्रंप का युग है। जलवायु परिवर्तन रोकने के प्रयासों का विरोध पहले से हो रहा है और यह बढ़ता ही जाएगा चाहे दुनिया को बढ़ती गर्मी का कितना ही खराब असर क्यों न झेलना पड़े। गर्म होती दुनिया में अमीर तगड़े नुकसान झेलेंगे, बीमा कराने वाले इन आपदाओं से सुरक्षा हासिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी कीमत बढ़ती जाएगी और बीमा कंपनियां अपना हाथ खींच लेंगी।

यह सब लिखने के पीछे मेरी मंशा यह बताने की नहीं है, जो सामने आता दिख रहा है बल्कि उन कामों की ओर ध्यान दिलाने को लिख रही हूं, जो जलवायु के जोखिम कम करेंगे और हमारी दुनिया की आजीविका तथा अर्थव्यवस्थाओं को सुधारेंगे। इस वक्त कार्बन उत्सर्जन कम करने की राह पर चलते हुए समावेशी और सतत विकास के लाभ हासिल करना बड़ी चुनौती है। उत्सर्जन कम करना विकासशील देशों के लिए ज्यादा कारगर और अहम है।

स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की बात ही ले लीजिए। भारत के लिए लाखों लोगों की आजीविका सुरक्षित करने के मकसद से बिजली देना जरूरी है। आज भी देश में बड़ी संख्या में परिवार बिजली की किल्लत झेल रहे हैं। उन्हें या तो बिजली की भरोसेमंद आपूर्ति नहीं होती या बिजली उपलब्ध ही नहीं होती और होती भी है तो बहुत महंगी पड़ती है। कई लोग तो आज भी बिजली की लाइट नहीं जला पाते और उनके परिवार की महिलाएं उपले या कोयले से खाना बनाने को मजबूर हैं।

दूसरी ओर उद्योग भी इससे प्रभावित हो रहा है और तब हो रहा है, जब ऊर्जा पर आने वाला खर्च तय करता है कि उद्योग कितनी होड़ कर सकता है। यही कारण है कि भारतीय उद्योग कोयले जैसा ईंधन इस्तेमाल कर खुद बिजली बनाना (कैप्टिव पावर) पसंद करता है। इसलिए हमें अधिक ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा और सस्ती ऊर्जा के लिए नीतियां बनानी होंगी। अगर ऊर्जा का परिवर्तन सही तरीके से करा लिया गया तो हम कार्बन के कम उत्सर्जन के साथ विकास की राह पर बढ़ सकते हैं, जो हमारे लिए कारगर होगा और दुनिया को तबाही की ओर ले जा रहे उत्सर्जन को कम करेगा।

इसीलिए 2030 तक 500 गीगावॉट स्वच्छ बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने की सरकार की योजना सराहनीय है। सरकार जानबूझकर कोयले को पूरी तरह नहीं हटा रही क्योंकि अब भी 75 फीसदी बिजली कोयले से बनती है। सरकार चाहती है कि कोयले की जगह किसी और स्रोत से स्वच्छ बिजली बनाई जाए। इसके लिए सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो 2030 तक बिजली की 44 फीसदी मांग पूरी कर सकती है। इसके लिए स्वच्छ ऊर्जा दोगुनी से भी ज्यादा करनी होगी क्योंकि इसी दरम्यान भारत की बिजली की खपत भी दोगुनी हो जाएगी। सरकार स्वच्छ बिजली की तरफ बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

लेकिन हमें गैर-जीवाश्म स्रोतों से बिजली तैयार करने की भारत की क्षमता को ठीक से समझना होगा। भारत में आज 200 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है, जो मार्च 2024 में देश की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता की 45 फीसदी थी। मगर कुल ऊर्जा उत्पादन में इस क्षमता का बमुश्किल एक चौथाई योगदान ही रहा। अगर आप निवेश और स्थापना के मामले में साल दर साल तेजी से इजाफा करने वाले पवन और सौर ऊर्जा स्रोतों को ही देखें तो वे भी 13 फीसदी बिजली ही बना पाए। ऐसे तो हम स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते नहीं दिखते। सरकार ने खुद कहा है कि कोयले की जगह लेने के लिए इन दो स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को 2030 तक 30 फीसदी बिजली बनानी पड़ेगी।

क्या सौर और पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता और उनसे हो रहे उत्पादन में फर्क है? यदि हां, तो क्यों? इसके लिए देखना होगा कि चालू संयंत्रों की कितनी क्षमता का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यह आंकड़ा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के संयंत्रों के लिए ही मिल सकता है निजी क्षेत्र के पवन और सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए नहीं। वास्तव में इस बात के सार्वजनिक आंकड़े ही नहीं हैं कि देश में कितनी इकाइयां शुरू की गईं, कितनी बिजली बनती है और बिजली कहां बेची या भेजी जाती है। विडंबना है कि ताप ऊर्जा संयंत्रों की यह जानकारी मिल जाती है नई ऊर्जा की नहीं।

लगता है कि इस निजी उद्योगों और निवेशकों वाले इस कारोबार में सबने चुप रहने की ठान ली है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) की वेबसाइट बताती है कि जून 2024 तक कई परियोजनाएं शुरू ही नहीं हुई थीं जबकि उनके बिजली खरीद समझौतों के मुताबिक परियोजना का ठेका तभी दिया जाता है, जब बिजली खरीद समझौता हो जाता है यानी एक तय कीमत पर बिजली खरीदने की बात पक्की हो जाती है। यह भी तब होता है जब परियोजना शुरू करने वाली कंपनी बता देती है कि उसके पास निवेश, जमीन और दूसरी सुविधाएं हैं। सेकी के अनुसार ऐसी 34.5 गीगावॉट की सौर, पवन और हाइब्रिड परियोजनाएं हैं।

उनके अलावा 10 गीगावॉट या ज्यादा (सरकारी आंकड़ा नहीं हैं मगर उद्योग का अनुमान है) की परियोजनाओं को बिजली खरीद समझौते (पीपीए) का इंतजार है। ये इसलिए अटकी हैं क्योंकि राज्य की बिजली खरीद एजेंसियां बताई जा रही कीमत पर समझौता करने को राजी नहीं हैं। यह तब हो रहा है जब नई कोयला परियोजना से मिलने वाली बिजली सौर परियोजना की बिजली से महंगी पड़ती है। इसकी एक वजह यह बताई जाती है कि सौर और पवन ऊर्जा हमेशा नहीं मिलतीं। दोनों तभी मिलेंगी, जब धूप खिलेगी और हवा चलेगी। इसलिए ऐसी परियोजनाएं बनाई जाएं जो 24 घंटे बिजली दे सकें चाहे बैटरी स्टोरेज के साथ हो या ज्यादा क्षमता वाले संयंत्र लगाकर। लेकिन सेकी के मुताबिक ये परियोजनाएं 'फंसी' हुई हैं और शुरू नहीं हो रही हैं। भारत को 500 गीगावॉट स्वच्छ बिजली का लक्ष्य पूरा करना है तो हमें ये कमियां दूर करनी होंगी। यह वाकई बहुत जरूरी है।

आपका पक्ष

डिजिटल क्रांति एआई और समावेशी विकास का युग

भारत की डिजिटल क्रांति देश के हर कोने में फैल रही है। बारामती के एक छोटे किसान से लेकर महाकुंभ के विशाल आयोजन तक तकनीक ने हमारे जीवन को बदल दिया है। यह क्रांति केवल शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांवों और कस्बों में भी अपनी छाप छोड़ रही है। डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) इस क्रांति का आधार है। यूपीआई और डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भारत की बढ़ती ताकत ने हमें वैश्विक मंच पर एक महत्त्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) इस क्रांति का एक और महत्त्वपूर्ण पहलू है। सरकार एआई को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए काम कर रही है। कॉमन कंप्यूट सुविधा और

डिजिटल क्रांति केवल शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांवों और कस्बों में भी अपनी छाप छोड़ रही है

भारत का कार्यबल इस डिजिटल क्रांति का केंद्र है। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार एआई, 5जी और सेमी-कंडक्टर डिजाइन को शामिल करने के लिए विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में बदलाव कर रही है। यह क्रांति केवल तकनीक के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे लोगों के बारे में भी है। यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक अवसर है। भारत एक उज्ज्वल डिजिटल भविष्य की ओर अग्रसर है।

राजूराम प्रजापत, नागौर

चीन ने बढ़ाया रक्षा बजट

चीन ने अपने रक्षा बजट में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 249 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया है, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सैन्य संतुलन को प्रभावित कर सकता है। यह केवल सैन्य विस्तार नहीं, बल्कि उसकी वैश्विक प्रभुत्व की रणनीति का हिस्सा है। चीन अपनी सेना को अत्याधुनिक युद्धपोतों, मिसाइल तकनीक और लड़ाकू विमानों से लैस कर रहा है, जिससे उसकी आक्रामक सैन्य नीति और तेज हो सकती है। भारत के लिए यह केवल चेतावनी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनने का अवसर भी है। भारत को अपने रक्षा बजट के कुशल उपयोग, स्वदेशी रक्षा उत्पादन और सैन्य आधुनिकीकरण पर जोर देना होगा। 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत हमें रक्षा उपकरणों का स्वदेशी उत्पादन तेजी से बढ़ाना चाहिए, ताकि बाहरी निर्भरता कम हो। साथ ही अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों के साथ सामरिक सहयोग को मजबूत करना होगा, जिससे भारत की रणनीतिक स्थिति सशक्त हो। इसके अलावा सीमा सुरक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। चीन का यह सैन्य विस्तार सिर्फ प्रतिस्पर्धा ही नहीं, बल्कि संभावित संघर्ष का संकेत भी देता है। भारत को अब केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय दीर्घकालिक सैन्य रणनीति पर काम करना होगा। यह समय सतर्कता और आत्मनिर्भरता दोनों बढ़ाने का है, ताकि भारत सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में रविवार को बेंगलूरु स्थित एयरक्राफ्ट डिविजन में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमकेए का पहले रियर फ्यूजीलाज हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपा गया। इसका निर्माण अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। इस

चिंतन

खालिस्तान समर्थक विदेशी सरजमीं पर फैला रहे फन

विदेशों में भारत विरोधी ताकतें लगातार फन फैला रही हैं। पांच दिन पूर्व विदेश मंत्री एस. जयशंकर की गाड़ी को लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने घेर लिया। उनमें से एक ने उनकी गाड़ी के सामने आकर देश की शान तिरंगे झंडे को भी फाड़ा। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। अब अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई और उस पर आपत्तिजनक नारे लिखे गए। ये घटना चिनो हिल्स इलाके में हुई। आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा भारतीय दूतावासों, प्रवासियों और मंदिरों पर हमलों का सिलसिला साफ दर्शाता है कि यह सब सुनियोजित अभियान के तहत हो रहा है, जिसका लक्ष्य पंजाब में अलगाववादी ताकतों को पुनर्जीवित करना है। पश्चिमी देशों को अड्डा बनाकर उग्रवादी प्रचार, वित्तीय अनुदान और हिंसक गतिविधियों को तेज करके पंजाब में दोबारा नफरत की आग लगाने की चेष्टा हो रही है। परेशानी केवल इतनी नहीं है कि खालिस्तानी अतिवादियों को पश्चिमी देशों में शरण मिल रही है, बल्कि यह भी है कि वहां की सरकारें इस खतरे की अनदेखी कर रही हैं, उन्हें सुरक्षा माहौल भी दिया जा रहा है। इस पूरे फसाद की जड़ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआई का सहयोग साफ दिखाई दे रहा है। यह मामला गिने-चुने सिरफिरे खालिस्तानी कट्टरपंथियों का नहीं, बल्कि भारत के विरुद्ध एक बड़े विदेशी षड्यंत्र का है। खालिस्तानियों पर विदेशों में भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां पैनी नजर रखती आई हैं। ऐसे तत्वों के नापाक मंसूबों की जानकारी भी समय-समय पर संबंधित देशों को दी गई, लेकिन इनके खिलाफ कोई गंभीर कार्रवाई नहीं हो पाई। यहां तक कि कनाडा में तो वहां की सरकार ही इनके समर्थन में खड़ी नजर आई। कुछ ब्रिटिश गुरुद्वारों में खालिस्तान समर्थकों की ओर से भारत के खिलाफ चंदा इकट्ठा करने और खालिस्तान को लेकर जनमत संग्रह के बारे में भी भारतीय एजेंसियों ने विदेशी एजेंसियों को आगाह किया। बीते कुछ वर्षों में खालिस्तान समर्थकों ने कई देशों में ऐसे जनमत संग्रह आयोजित किए हैं, जिनमें ब्रिटेन, कनाडा, और अमेरिका शामिल हैं। ये आयोजन अक्सर विवादास्पद होते हैं और भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देते हैं। ऐसे जनमत संग्रह पंजाब को मुक्त करने के नाम पर आयोजित किए जाते हैं। भारतीय एजेंसियां कई षड्यंत्रों का भंडाफोड़ इसलिए नहीं कर पातीं, क्योंकि जिन देशों में ऐसी गतिविधियां संचालित होती हैं, वे खालिस्तान समर्थकों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं मानते। इन देशों में अधिकाधिक ध्यान इस्लामिक जिहादी आतंक पर दिया जाता है और रत्ती भर भी खालिस्तान से जुड़ी गतिविधियों पर नहीं रहता। खालिस्तान समर्थकों को खुली छूट है, क्योंकि वे इन देशों के नागरिकों और अधिष्ठानों पर हमले नहीं करते। ऐसे में भारत इन देशों में और क्या करे जिससे हमारे सरोकारों को लेकर जागरुकता और समानुभूति बढ़े? वास्तव में, हमें इस मुद्दे को पश्चिमी देशों के साथ 'सामरिक साझेदारी' और सहयोग का अहम विषय बनाना होगा। जिन देशों ने भारत के साथ 'खुफिया साझेदारी' पर सहमति जताई है, उन्हें खालिस्तानी-पाकिस्तानी मिलीभगत पर केंद्रित संयुक्त कार्रवाई को प्राथमिकता देने के लिए तैयार करना होगा। इन देशों से दो टूक बात करनी होगी कि अगर उनकी सरजमीं पर भारत के खिलाफ कोई गतिविधि होती है तो इसका असर सीधा दोनों देशों के रिश्तों पर होगा। तभी हम इन पर लगाम लगा सकते हैं।

दो टूक
प्रमोद भार्गव

गुलाम कश्मीर की वापसी ही समाधान

> अब हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, जब कश्मीर के उस हिस्से की वापसी होगी, जिस पर अवैध तौर से पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। इस हिस्से के कश्मीर में आते ही इस समस्या का समाधान पूरी तरह हो जाएगा। पाकिस्तान सरकार गुलाम जम्मू-कश्मीर के लोगों को विदेशी मानती है, बावजूद भारतीय कश्मीर को हथियाने की होड़ में लगी रहती है। गुलाम कश्मीर के हिस्से में गिलकिट-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और मीरपुर आते हैं। पाकिस्तान रणनीतिक रूप से गिलगिट-बाल्टिस्तान को पांचवां प्रांत बना लेने की फिराक में लगा है। पाकिस्तान यहां सुन्नी मुसलमानों की संख्या बढ़ाकर इस पूरे क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व बदलने के प्रयास में भी लगा है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कश्मीर के हालात और भारत सरकार की तरफ से उठाए गए संवैधानिक कदमों के बारे में लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक में 'विश्व में भारत का उदय और भूमिका' विषय पर बोलते हुए कहा कि कश्मीर के विवाद का समाधान कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी के बाद संभव हो जाएगा। भारत का यह हिस्सा अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है। वैसे हमने कश्मीर के सिलसिले में ज्यादातर मुद्दों का हल निकाल लिया है। इस बाबत कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद-370 का समापन पहला कदम था। कश्मीर में विकास, आर्थिक गतिविधि और सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा कदम था।

तीसरा कदम कश्मीर में भारतीय संविधान में निहित लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार चुनाव कराना था। इसमें मत प्रतिशत का अच्छा होना इस बात की तस्दीक है कि जम्मू-कश्मीर की जनता भारतीय लोकतंत्र का समर्थन कर रही है। अब हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, जब कश्मीर के उस हिस्से की वापसी होगी, जिस पर अवैध तौर से पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। इस हिस्से के कश्मीर में आते ही इस समस्या का समाधान पूरी तरह हो जाएगा। पाकिस्तान सरकार गुलाम जम्मू-कश्मीर के लोगों को विदेशी मानती है, बावजूद भारतीय कश्मीर को हथियाने की होड़ में लगी रहती है। गुलाम कश्मीर के हिस्से में गिलकिट-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और मीरपुर आते हैं। भारत की आजादी के पहले कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था। यहां डोगरा राजपूत वंश के राजा हरिसिंह शासक थे। कश्मीर में मुसलमानों की आबादी अधिक थी। इसलिए पाकिस्तान का मानना था कि कश्मीर उसके अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। इस मानसिकता के चलते पाक ने कश्मीर राज्य पर पाकिस्तान में विलय का नाजायज दबाव बनाया। लेकिन हरिसिंह इस दबाव में नहीं आए। तब 1948 में पाकिस्तान की सेना ने कबाइलियों के वेश में कश्मीर पर हमला कर दिया। किंतु हरिसिंह की समय पर भारतीय सेना ने मदद की और पाक सेना को न केवल खदेड़ दिया, बल्कि संपूर्ण कश्मीर के एक तिहाई हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। इसी बीच कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में पहुंचा और 5 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। युद्ध विराम के वक्त जो सेनाएं जिस भूमि पर थीं, उसे ही युद्ध विराम की रेखा मान लिया गया। यही आज नियंत्रण रेखा (एलओसी) मानी जाती है। इस कारण पीओके जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, वह पाकिस्तान के हिस्से में है और श्रीनगर समेत शेष कश्मीर भारत के हिस्से में है। किंतु अब कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद शांति और विकास की हवा चल पड़ी है और कश्मीरी स्वयं आतंकियों की घुसपैठ की खबर स्थानीय पुलिस और सेना को देने लगे हैं।

इन युद्धों और आतंकी घुसपैठियों की मदद में पाकिस्तान इतना धन और हथियार बर्बाद कर चुका है कि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। दूसरी तरफ जिस आतंकवाद का जनक पाकिस्तान रहा है, वही आतंकवाद उसके लिए अब पीओके में चुनौती बनकर सामने आ रहा है। पाक में आतंकी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बलूचिस्तान प्रांत के तुरबाद नगर में नौसैनिक अड्डे पर आतंकवादियों ने गोली बरसाते हुए

हमला किया। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा इलाके में चीनी नागरिकों के एक काफिले पर हमला बोल दिया। इसमें पांच चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी। इन हमलों की जुम्मेबारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) की मजीद ब्रिगेड ने ली है। इस्लामाबाद से 200 किमी दूर स्थित दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण चीनी कंपनी कर रही है। 2021 में भी इस परियोजना पर काम कर रहे नौ चीनी इंजीनियरों सहित 13 लोगों को बलूच हमलावरों ने मार गिराया था। दरअसल बलूचिस्तान प्रांत के नागरिक मानते हैं कि पाक सरकार उनके प्रांत के हितों की लंबे समय से अनदेखी कर रही है। यहां के लोग इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप का भी विरोध कर रहे हैं। दासू हाइड्रोप्रेजेक्ट और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के निर्माण के अंतर्गत कई परियोजनाएं पीओके में निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं का विरोध लगातार हो रहा है। लेकिन पाक सरकार धन के लालच में चीन के सुरसामुख में फंस चुकी है। देश में चल रही आर्थिक बदहाली के कारण भी सरकार चीन का दामन नहीं छोड़ पा रही है। चीन से उसकी मित्रता का कारण धन का लालच तो है ही, भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्ते भी हैं। पाक की तरह चीन से भी भारत का सीमा पर निरंतर तनाव बना हुआ है। अब पीओके में आतंकी शक्तियां इतनी मजबूत हो गई हैं कि पाक का ईरान और अफगानिस्तान से भी मधुर संबंध बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। पीओके की परिधि में आने वाले गिलगिट-बाल्टिस्तान वास्तव में भारत के जम्मू-कश्मीर राज्य के हिस्से हैं। बावजूद पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में हैं। लेकिन यहां के नागरिकों ने इस बलात कब्जे को कभी नहीं स्वीकारा। यहां तभी से राजनीतिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक आवाजें उठ रही हैं और पाक सरकार इन लोगों पर दमन और अत्याचार का सिलसिला जारी रखे हुए है। साफ है, पाक की आजादी के साथ गिलगिट-बाल्टिस्तान का मुद्दा जुड़ा हुआ है। पाक की कुल भूमि का 40 फीसदी हिस्सा यहीं है। इस हिस्से में सर्वाधिक बलूच हैं, इसलिए इसे गिलगिट-बलूचिस्ताल भी कहा जाता है। निर्वाचन की प्रक्रिया से गुजरने के बावजूद यहां की विधानसभा को अपने बूते कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। सारे फैसले एक परिषद लेती है, जिसके अध्यक्ष पाकिस्तान के पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। लिहाजा चुनाव के बावजूद भी यहां विद्रोह की आग सुलगी रहती है। यह आग अस्तोर, दियामिर और हुनजा समेत उन सब इलाकों में सुलगी रहती है, जो शिया बहुल हैं। सुन्नी बहुल पाकिस्तान में शिया और अहमदिया मुस्लिमों समेत सभी धार्मिक अल्पसंख्यक प्रताड़ित किए जा रहे हैं। यअहमदिया मुस्लिमों के साथ तो पाक के मुस्लिम समाज और हुकूमत ने भी ज्यादती बरती है। 1947 में उन्हें गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया था। तब से वे न केवल बेगाने हैं, बल्कि हिंदू, सिख व ईसाइयों की तरह मजहबी चरमपंथियों के निशाने पर भी रहते हैं।चीन की एक और बड़ी योजना है,'चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर' जिसकी लागत 3 लाख 51 हजार करोड़ है। यह गलियारा गिलगिट-बाल्टिस्तान से गुजर रहा है। इस गलियारे के निर्माण में लगे चीनी नागरिकों की आतंकी संगठन बीएलए हत्याएं कर रहा है। चूंकि यह क्षेत्र अधिकारिक रूप से भारत का है, इसलिए भारत भी इस परियोजना का लगातार विरोध कर रहा है। पाकिस्तान रणनीतिक रूप से गिलगिट-बाल्टिस्तान को पांचवां प्रांत बना लेने की फिराक में लगा है। पाकिस्तान यहां सुन्नी मुसलमानों की संख्या बढ़ाकर इस पूरे क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व बदलने के प्रयास में भी लगा है। इन कारणों के चलते यहां के मूल बलूचों की पाकिस्तान के प्रति जबरदस्त नाराजगी है और वे निर्णायक लड़ाई लड़कर भारत में विलय होने की कोशिश में लगे हैं।

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं। लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।)

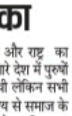

पुण्यतिथि विशेष
हर्षवर्धन पाण्डे

सावित्रीबाई फुले : देश की पहली महिला शिक्षिका

शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे हम अपना और राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। वैसे तो पुरातन काल में हमारे देश में पुरुषों को ही शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति दी जाती थी लेकिन सभी पुरानी जंजीरों को तोड़ते हुए महिलाओं को शिक्षा देने के उद्देश्य से समाज के सामने देश की सबसे पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का विलक्षण व्यक्तित्व सामने आता है। एक दौर में जब महिलाओं को घर की चारदीवारी में कैद रखा जाता था, सावित्रीबाई फुले ने समाज की रूढ़िवादी मान्यताओं को चुनौती देते हुए नारी सशक्तिकरण का बिगुल बजाया। महज नौ वर्ष की उम्र में विवाह बंधन में बंधी सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर समाज सुधार के अनेक कार्य किए। वह भारत की पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारक थीं, जिन्होंने महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए कड़ा संघर्ष किया। उनके प्रयासों से शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और शैक्षणिक क्रांति की नींव पड़ी। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को पुणे के नजदीक नायगांव में हुआ था। उन्होंने न केवल महिलाओं के शिक्षा अधिकार की वकालत की, बल्कि समाज के उत्पीड़ित वर्गों के लिए भी कार्य किया। सावित्रीबाई ने अपनी शादी के बाद ही शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा और एक नई दिशा की ओर बढ़ी। 1 जनवरी 1848 को सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। यह उस समय सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध एक क्रांतिकारी कदम था। इस पहल का रूढ़िवादी समाज ने घोर विरोध किया। उन्हें अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे-धीरे फुले दंपति ने पुणे और उसके आसपास के गांवों में 18 स्कूलों की स्थापना की। सावित्रीबाई जब पढ़ने स्कूल जाती थीं तो लोग उन्हें पत्थर, कूड़ा और कीचड़ फेंकते थे। वह अपने साथ एक जोड़ी कपड़ा साथ लेकर जाती थीं और स्कूल पहुंचकर गोबर और कीचड़ से गंदे हो गए कपड़ों को बदल लेती थीं। उन्होंने हिम्मत नहीं और और हर चुनौती का सामना किया। पढ़ने के बाद उन्होंने दूसरी लड़कियों और दलितों के लिए एजुकेशन पर काम करना किया। सावित्रीबाई फुले को शिक्षा के क्षेत्र में महान योगदान देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। सावित्रीबाई फुले ने अपनी शिक्षा प्रणाली में जातिवाद, धर्मवाद और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने सिखाया कि शिक्षा केवल एक व्यक्ति की क्षमता का निर्माण नहीं करती, बल्कि यह समाज को भी एक बेहतर दिशा में मार्गदर्शन देती है। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। सावित्रीबाई ने 1854 में 'सीनियर स्कूल' में दलित बच्चों को भी शिक्षा देने की पहल की थी। इससे यह साबित हुआ कि उनके लिए किसी भी जाति या धर्म के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार समान था। उन्होंने यह भी सिखाया कि समाज में लैंगिक समानता और अधिकारों की स्थिति को लेकर पुरुषों और महिलाओं को एक समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। महाराष्ट्र में 1875 से 1877 के बीच बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। सभी बहुत बीमार पड़ रहे थे। सावित्रीबाई ने सत्यशोधक समाज नाम के एक समूह का नेतृत्व किया। इस समूह के लोगों ने बहुत सारे बीमार लोगों की मदद की। सत्यशोधक समाज के लोग बिना किसी पंडित या पुजारी के शादियां करवाते थे। 1896 में महाराष्ट्र में दोबारा बहुत बड़ा अकाल पड़ा। इस दौरान सावित्रीबाई को पता चला कि उनके दोस्त पांडुरंग बाबाजी गायकवाड़ का बेटा बहुत बीमार है। सावित्रीबाई तुरंत उनके पास गईं और बीमार बच्चे को अपनी पीठ पर उठाकर डॉक्टर के पास ले गईं। इस दौरान खुद सावित्रीबाई भी बीमार हो गईं। उन्हें प्लेग नाम की बीमारी हो गई थी। इसी बीमारी की वजह से 10 मार्च, 1897 को सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया।

सावित्रीबाई फुले की यात्रा यह सिखाती है कि जब तक समाज में समानता और न्याय नहीं आता, तब तक निरंतर संघर्ष करना आवश्यक है। उनके द्वारा किए गए कार्यों ने न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया में महिलाओं और उत्पीड़ित वर्गों के लिए एक नया रास्ता खोला। उनकी निडर भावना और यथास्थिति को चुनौती देने का दृढ़ संकल्प अविश्वसनीय है। हर तरह के दमन और भेदभाव के खिलाफ उनकी लड़ाई प्रशंसनीय है। फुले ने महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता का जो अमूल्य उपहार दिया, उसकी बदौलत वह आज भी याद की जाती हैं। उनके जीवन ने यह साबित किया कि समर्पण, लगन और संघर्ष से समाज की हर बाधा को पार किया जा सकता है। महिला शिक्षा को लेकर उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।

आपके भीतर है आनंद, जिसे बाहर न खोजें

संकलित
दर्शन

कल्पना क्या है और सच्चाई क्या है! इसे समझने के लिए आपकी जड़ का मजबूत होना जरूरी है। सारी कल्पनाएं आपके अंदर हैं। यह कल्पना नहीं है, यह सच है। कल्पना में डूबना बड़ा आसान है, सच्चाई को जानना बहुत मुश्किल है। जिसको आप खोज रहे हैं, वह आपके अंदर है। उसे जानिए, पहचानिए, उसके साथ थोड़ा समय बिताइए, क्योंकि उसमें सबकुछ है। जो आपके भीतर है, वह है शांति। किसी चीज का न होना शांति नहीं है। किसी चीज का होना शांति है। जब मनुष्य खुद को जानेगा, खुद को समझेगा, तब उसके जीवन में शांति होगी। जैसे भोजन खा लेने पर भूख खत्म होती है, उसी प्रकार खुद को जान लेने पर तृष्णा मिट जाती है। शांति मिल जाती है। सोचें कि यह शरीर आपको क्यों मिला है? जिन तत्वों से शरीर बना है, वे सारे तत्व वहीं वापस चले जाएंगे जहां से ये आये थे। जिस तरह पानी, पानी में मिल जाता है। सारी चीजें प्रकृति में घुल जाएंगी। क्या समझते हैं आप कि जब बच्चा पैदा होता है तो इस धरती का वजन बढ़ता है! या जब कोई मर जाता है तो इस धरती का वजन कम होता है! वजन न तो बढ़ता है न कम होता है। क्योंकि जिन चीजों से आप बने हुए हैं वे तो अभी यहीं हैं। परंतु क्या आपने उस चीज को जाना, समझा जो आपके शरीर के अंदर है? इसे जान गए, पहचान गए, फिर आनंद ही आनंद है। आपका नाम आपके शरीर का नाम है। नाम कमाने से क्या होगा। नाम नहीं, ज्ञान कमाइये। आनंद कमाइए। ये आप अपने साथ ले जा सकते हैं। जहां जाएंगे, वहां ले जा सकते हैं।

ऐसे काम न करें, जिससे गलत लोगों की ताकत बढ़े

संकलित
प्रेरणा

बाल कृष्ण माखन चोरी की लीला कर रहे थे। गोकुल के लोग इस वजह से काफी परेशान थे। एक दिन गांव के नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचे और कान्हा की शिकायत करने लगे। नंद बाबा ने कृष्ण से पूछा कि तुम माखन चोरी क्यों करते हो, जबकि हमारे घर में तो बहुत माखन है। कृष्ण ने कहा कि आप लोग मेहनत से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हैं और फिर ये चीजें कर के रूप में दुष्ट कंस को दे देते हैं और इस वजह से गांव के बच्चों को माखन नहीं मिलता है। आपके इस काम से कंस की ताकत लगातार बढ़ रही है। अगर आप कंस को कर देना नहीं रोकेंगे तो मैं तोड़-फोड़ करता रहूंगा। ताकि ये माखन कंस के पास न पहुंचे और गांव के बच्चों को मिल सके। कंस गांव के लोगों से कर के रूप में दुध, मक्खन वसूला करता था। कृष्ण ने देखा की लोग अपने बच्चों को न देकर कर के रूप में मक्खन कंस को देते हैं। कृष्ण ने इस बात का विरोध किया। ताकि लोग अपनी ताकत समझ सके और मिलकर कंस का विरोध कर सके। इस कथा में श्रीकृष्ण ने संदेश दिया है कि हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए, जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती है। और व हम पर हावी हो जाए।

यूर उत्सव

लाहौल-स्पीति जिले के मडग्रां में रविवार को यूर उत्सव के दौरान ग्रामीण बर्फ के 12 फीट ऊंचे शिवलिंग के पास अनुष्ठान करते हुए।

आज की पाती

महिलाओं को विकास के समान अवसर दे

सृष्टि की जब से रचना हुई है, इस पूरे संसार को सजाने व संवारने का काम मात्र दो ही प्राणियों ने किया है और वे दो प्राणी हैं- पुरुष एवं स्त्री। परंतु समस्त संसार की रचना में दो प्राणियों में भी अगर सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है तो वह एक स्त्री का, एक औरत का, एक नारी का, क्योंकि वह समस्त संसार की जननी है, समस्त संसार की उत्पति उसकी कोख से होती है, या यूं कह ले कि स्त्री के बिना सांसारिक रचना की कल्पना मात्र भी नहीं की जा सकती है। यह भी कहा जाता है कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक सफल औरत का हाथ होता है। संसार भर में औरतों के सम्मान के लिए एक दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए समर्पित है। इस दिवस को मनाने का औचित्य तभी है, अगर महिलाओं को विकास के समान अवसर दे दिए जाएं। - विनय कुमार साहू

ट्रेंड

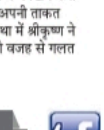

वन्यजीवों की रक्षा

भारत वन्यजीव विविधता और वन्यजीवों का जश्न मनाने वाली संस्कृति से धन्य है। हम हमेशा जानवरों की रक्षा करने और एक स्थायी ग्रह में योगदान देने में सबसे आगे रहेंगे।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

पुस्तकें विरासत की वाहक

पुस्तकें केवल ज्ञान की स्रोत ही नहीं, बल्कि परंपरा व विरासत की वाहक भी होती है। आज अहमदाबाद में सस्तु साहित्य मुद्रणालय द्वारा साल 2024-25 में पुनः प्रकाशित 24 पुस्तकों का विमोचन किया। सस्तु कम कीमतों में पुस्तकों का प्रकाशन कर आर्थिक बाधाओं को समाप्त करने में अहम योगदान दे रहा है।

-अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

मिलकर खुशियां बांटें

होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, सौहार्द और सामाजिक एकता का प्रतीक है! आइए, इन रंगों के साथ मिलकर खुशियाँ बाँटें और प्रेम का यह सिलसिला यूं ही बना रहे !

-रेखा गुप्ता, सीएम, दिल्ली

दिल से जुड़ा रिश्ता

मैं अपने और दर्शकों के बीच एक दिल से जुड़ा रिश्ता बनाने की कोशिश करता हूं। लेकिन अब उन्हें आंकड़ों की तरह देखा जाता है। उन लोगों द्वारा जो मेरे और मेरे चाहने वालों के बीच द्वारपाल बन गए हैं।

-शेखर कपूर, फिल्मकार

करंट अफेयर

ओडिशा के द्वीप पर 33 साल बाद दिखे ओलिव कछुए

ओडिशा के गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य के एकाकुलानासी द्वीप पर लुप्तप्राय ओलिव रिडले कछुए फिर से दिखाई दिए हैं। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि 33 वर्षों के अंतराल के बाद यह कछुए सामूहिक रूप से अंडे देने और उन्हें सेने के लिए आए हैं। सहायक वन संरक्षक मानस दास ने कहा, 'द्वीप का रमणीय समुद्र तट समुद्री कटाव से प्रभावित हुआ, जिसके कारण समुद्र तट का स्वरूप छोटा हो गया। हालांकि, 2020 से इसमें वृद्धि शुरू हुई और अब समुद्र तट का पहले की तुलना में विस्तार हुआ है। यह कछुओं के लिए अंडे देने के लिए सामूहिक रूप से आने के लिए अनुकूल साबित हुआ है।' दास ने कहा कि कछुओं की यह समुद्री प्रजाति आखिरी बार 1992 में समुद्र तट पर दिखाई दी थी, जब तीन लाख कछुओं ने अंडे दिए थे। उन्होंने कहा, 'यह ओडिशा वन विभाग के नेतृत्व में चल रही कछुआ संरक्षण पहल में एक अत्यंत सकारात्मक प्रगति है।' हर साल ओडिशा तट पर लाखों की संख्या में ओलिव रिडले कछुए सामूहिक रूप से अंडे देने के लिए आते हैं।

ऑफ बीट

अकेलापन समझने के तरीके को बदल देता है

अगर कोई एक चीज है जो इंसानों के रूप में हम सब में एक जैसी है, तो वह यह है कि हममें से अधिकांश ने कभी न कभी अकेलापन महसूस किया है।

लेकिन क्या सामाजिक रूप से अलग-थलग महसूस करने से होने वाला दर्द इंसान होने का एक हिस्सा है? जब हम अकेलापन महसूस करते हैं तो दुनिया इतनी अलग क्यों लगती है? हाल के शोध ने कुछ उत्तर देना शुरू कर दिया है। और यह पता चला है कि अकेलापन आपकी धारणा और संज्ञान को प्रभावित कर सकता है।अध्ययनों ने अकेलेपन से जुड़े मस्तिष्क क्षेत्रों में अंतर की पहचान की है। अकेले युवा वयस्कों में, सामाजिक अनुभूति और सहानुभूति से संबंधित मस्तिष्क के क्षेत्रों में कम घना सफेद पदार्थ (तंत्रिका तंतुओं का एक बड़ा नेटवर्क जो आपके मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सूचना और संचार के आदान-प्रदान का काम करता है) होता है। लेकिन अकेले वृद्ध वयस्कों में, संज्ञानात्मक प्रसंस्करण और भावनात्मक विनियमन के लिए महत्वपूर्ण मस्तिष्क क्षेत्र वास्तव में मात्रा में छोटे होते हैं। एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि अकेले लोगों का दिमाग दुनिया को अजीब तरीके से संसाधित करता है।

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbsanati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

महत्वपूर्ण अवसर

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है। लेकिन इसे एक तिथि तक सीमित कर दिया गया है। यह हमें ऐतिहासिक महिला संघर्षों तथा अभी मौजूद चुनौतियों की याद दिलाती है। खासकर भारतीय महिलाओं ने असाधारण आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना किया है। विश्व मंच पर वे अपने विशिष्ट साहस और प्रतिबद्धता से बने बनाए ढांचे तोड़ने में सफल हुई हैं और उन्होंने अनेक पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है जिन पर अंतर्निहित रूप से पितृसत्तात्मक समाज में ऐतिहासिक रूप से पुरुषों तथा थोड़ी सी महिलाओं का प्रभुत्व था। आज हम इन उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अभी भारतीय महिलाओं की सच्ची मुक्ति का काम जारी है और वास्तव में यह निरंतर यात्रा है। अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने का मार्ग सीमाबंधन वाले सामाजिक मानकों और जेंडर पूर्वाग्रहों से भरा है जिनको पार करना है। भारतीय महिलाओं को यह काम करना होगा। ऐतिहासिक रूप से चूल्हे चौके से बंधी महिलाओं की शिक्षा और कॅरियर विकल्पों तक सीमित पहुंच थी और भारतीय महिलाओं का रास्ता आसान नहीं था। आज समय के साथ जेंडर विभाजन कमजोर पड़ने के बावजूद आधुनिक भारतीय महिलाओं नेतृत्वकारी भूमिकाओं में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा की चिन्तायें, खासकर जेंडर-आधारित हिंसा और उत्पीड़न महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं जिनसे निपटने के लिए न केवल व्यवस्थागत परिवर्तन, बल्कि सड़ी-गली सोच में व्यापक परिवर्तन जरूरी हैं। सांस्कृतिक उम्मीदों ने महिलाओं पर बोझ डाला है, जिसके कारण अक्सर उनको पेशेवर आकांक्षाओं तथा परंपरागत पारिवारिक भूमिकाओं में संतुलन बनाना होता है। अक्सर इस दुहरी जिम्मेदारी के कारण कॅरियर से समझौता करना पड़ता है तथा अनेक महिलाओं को मातृत्व लाभ तथा लचीले कार्यस्थल परिवेश जैसे संस्थागत समर्थन के अभाव में कार्यबल से हटना पड़ता है। इन बाधाओं के बावजूद भारतीय महिलाओं ने अपनी दृढ़ता एवं उत्कृष्टता सिद्ध करते हुए पुरुष-प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में अपना स्थान बनाया है। एक समय केवल पुरुष प्रभुत्व वाले क्षेत्र सशस्त्र बलों में आज महिलायें फाइटर पाइलटों, कमांडिंग आफिसरों तथा फ्रंटलाइन योद्धाओं के रूप में काम कर रही हैं। बायोटेक्नोलोजी में किरन मजूमदार शॉ, उद्यमिता में फाल्गुनी नायर तथा खेलों में रानी रामपाल ने सफलता को पुनः परिभाषित करते हुए लाखों लोगों को प्रेरणा दी है। महिला पत्रकारों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने प्रमुखता प्राप्त की है जिनमें वाइरोलोजी में गगनदीप कांग से लेकर भारत की 'मिसाइल महिला' टेसी थामस तक शामिल हैं। भारतीय न्यायपालिका एक समय पूर्ण पुरुष प्रभुत्व वाली थी, पर अब उसमें महिला जज न्याय दे रही हैं। इनमें जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल हैं जो देश की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनेंगी। हालांकि, ये उपलब्धियां प्रशंसनीय हैं, पर सच्ची जेंडर समानता अभी आनी बाकी है। राजनीति और कार्पोरेट बोर्ड रूमों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून हैं, पर अक्सर उनका क्रियान्वयन कमजोर होता है। शिक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता महिला सशक्तीकरण हेतु आवश्यक है, लेकिन बहुत सी महिलाओं की अभी इन मूलाधिकारों तक पहुंच नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए नीतिगत सुधारों के माध्यम से समान वेतन, स्मार्ट कार्यस्थल तथा कॅरियर में प्रगति के अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए। सामाजिक सोच में परिवर्तन लाना जरूरी है जिसमें जेंडर समानता के समर्थन में पुरुष सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। स्कूलों में समावेशन के मूल्य पढ़ाए जाने चाहिए। शुरुआत से ही जेंडर समानता का विचार समाहित किया जाना चाहिए। लड़कियों से अक्सर उनके माता-पिता द्वारा किया गया भेदभाव निंदनीय है। यह भेदभाव अनेक स्तरों पर है और इसे इक्कीसवीं शताब्दी में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारत में महिला सहभागिता देश का भविष्य पुनः परिभाषित कर सकती है। नीति निर्माताओं, बिजनेसों तथा समाज के सामूहिक प्रयास से महिलाओं का उत्थान केवल विमर्श से आगे बढ़ कर दिन-प्रतिदिन का यथार्थ बन सकता है। यह रास्ता लंबा है, पर भारतीय महिलाओं ने बार-बार दिखा दिया है कि उनको रोका नहीं जा सकता है। महिला केवल परिवर्तन का हिस्सा न हो कर अपने आप में परिवर्तन है।

महिला सशक्तीकरण का लंबा रास्ता

महिला मुद्दों को हाशिए पर धकेलने के बजाय उनको नीति-निर्माण तथा प्रशासन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर हमें प्रतीकात्मक संकेतों तथा लफ्फाजी से आगे बढ़ना चाहिए।

प्रियंका चतुर्वेदी
(लेखिका, राज्यसभा सदस्य हैं)

राजनीति में शामिल महिला तथा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की पैरोकार के रूप में मैं इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अपनी हार्दिक शुभकामनायें व्यक्त करती हूं। यह अवसर न केवल उत्सव का, बल्कि हमारे द्वारा की गई प्रगति तथा सच्ची जेंडर समानता प्राप्त करने की दिशा में लंबे रास्ते पर विचार करने का समय है। इस वर्ष का महिला दिवस दिल्ली चुनाव के लगभग एक महीने बाद आया है जिसने चौथी महिला मुख्यमंत्री तथा पहली बार विपक्ष की महिला नेता नियुक्त कर इतिहास रचा है। हमने यहां अभूतपूर्व मतदान भी देखा जिसमें महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। 60.2 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में 60.9 प्रतिशत महिलाओं ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। दिल्ली में इस बार सबसे अधिक संख्या में महिलाओं ने चुनाव लड़ा जो कुल उम्मीदवारों में 14 प्रतिशत थीं। लेकिन यही बात निर्वाचित प्रतिनिधियों के बारे में नहीं कही जा सकती है।

महिलायें केवल 7 प्रतिशत सीटें प्राप्त कर सकीं जो एक दशक में सबसे कम थीं। इन आंकड़ों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व के रूप में देखने के पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि 2023 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए महिला आरक्षण कानून पास किया गया है। सभी पार्टियों का पूर्ण समर्थन मिलने के बावजूद यह कानून अभी अधर में लटका है और इसके क्रियान्वयन के पहले जनगणना तथा परिसीमन गतिविधियां पूर्ण होने की प्रतीक्षा है।

जनगणना को 2020 में स्थगित किया गया था और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इसमें अनिश्चितकालीन विलंब हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं का 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व एक दूर का सपना है, जबकि यथार्थ में यह 10-14 प्रतिशत के निकट बना हुआ है। यही पैटर्न हाल ही में समाप्त राज्य विधानसभा चुनावों में सामने आया है। यहां भी महिला उम्मीदवारों की संख्या 9 प्रतिशत थी तथा महाराष्ट्र विधानसभा में केवल 8 प्रतिशत महिलाओं को ही प्रतिनिधित्व मिला। इसी तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या 10 प्रतिशत थी, जबकि 14 प्रतिशत महिलायें विजय प्राप्त करने में सफल रहीं। झारखंड में महिला उम्मीदवारों की संख्या 11 प्रतिशत थी, जबकि 15 प्रतितशत महिला प्रतिनिधि चुनी गईं। हालांकि, हम राजनीति में ज्यादा महिला प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पर महिलाओं को लक्षित विमर्श प्रतिगामी बना हुआ है। अनेक राजनेताओं ने महिलाओं के पहनने वाले कपड़ों और उनके व्यवहार को लेकर महिला-विरोधी टिप्पणियां की हैं, जबकि स्वयं उनको ही अपना व्यवहार सुधारना चाहिए।

महिलाओं को ही लगातार उनके उत्पीड़न का जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि जेंडर-आधारित हिंसा का कारण बनने वाले ढांचागत मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। भारत में अब भी विवाह संबंधों में बलात्कार पर कोई कानून नहीं है। महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों पर लगाम लगाने वाला महाराष्ट्र का प्रस्तावित 'शक्ति विधेयक' केन्द्र की सहमति के बिना वापस कर दिया गया। जिस समाज में महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा बहस का विषय हो, वह समानता के रास्ते पर चलने का दावा नहीं कर सकता है। प्रतिनिधित्व में जेंडर अंतर राजनीति से आगे कार्पोरेट दुनिया तक जाता है। कंपनी बोर्डों में कम से कम एक महिला के प्रतिनिधित्व के प्रतीकवादी प्रयासों के बावजूद समानता की दिशा में प्रगति धीमी है।

भारत में कार्पोरेट कंपनियों के बोर्डों में महिलाओं को 2023 में केवल 18 प्रतिशत सीटें मिली थीं, जबकि इनका वैश्विक औसत 23 प्रतिशत है। इस संख्या में भी कंपनी बोर्डों की अध्यक्षता करने वाली महिलाओं की संख्या केवल 4 प्रतिशत है। उच्चतम कार्यकारियों के स्तर पर स्थिति और खराब है। दुनिया भर में केवल 6 प्रतिशत महिला सीईओ हैं, जबकि भारत में यह संख्या केवल 5 प्रतिशत है। मध्यवर्ती प्रबंधन भावी नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण होता है, पर यहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व घटा है। मध्यवर्ती प्रबंधन में 2019 में 18-19 प्रतिशत महिलायें थीं, पर कोरोनावायरस वैश्विक महामारी के बाद उनकी संख्या घट कर केवल 14-16 प्रतिशत रह गई। वरिष्ठ एवं मध्यवर्ती प्रबंधन में महिला कर्मचारियों का हिस्सा भारत में केवल 12.7 प्रतिशत है जो पड़ोसी देशों की तुलना में बहुत कम है। यह श्रीलंका में 24.6 प्रतिशत तथा थाईलैंड में 34.7 प्रतिशत है। महिला उद्यमियों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। महिला उद्यमियों के सूचकांक में भारत का 57वां स्थान है, जबकि केवल 20 प्रतिशत बिजनेसों का नेतृत्व ही महिलाओं के हाथ में है। फंडिंग में अंतर खासतौर से बहुत अधिक है। भारत में वेंचर कैपिटल की केवल 3 प्रतिशत फंडिंग ही 2021 में महिला-नीत स्टार्टअप को जाती थी। हालांकि, फंडिंग में यह असमानता केवल भारत की समस्या नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर भी महिला-नीत स्टार्टअप को वेंचर कैपिटल का बहुत थोड़ा हिस्सा मिलता है।

अमेरिका में महिलाओं का 40 प्रतिशत बिजनेसों पर स्वामित्व होने के बावजूद उनको केवल 2 प्रतिशत वेंचर फंडिंग मिलती है। यूरोप की भी यही स्थिति है जहां पुरुष-नीत स्टार्टअप लगातार निवेशों का बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। निवेश प्रक्रिया में जेंडर पूर्वाग्रह सुस्थापित है। प्रयोगों से पता चला है कि महिला के बजाय पुरुष नियंत्रण में होने पर समान प्रकार के स्टार्टअप को ज्यादा फंडिंग मिलने की संभावना होती है। निवेशक जहां पुरुष फंडर्स से वृद्धि संभावनाओं पर बात करते हैं, वहीं महिला उद्यमियों से उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं, जैसे वैवाहिक स्तर, बच्चों तथा बिजनेस के 'लाइफस्टाइल वेंचर' के बारे में पूछा जाता है।

व्यवस्थित व गहरे ये पूर्वाग्रह हर स्तर पर महिला प्रगति को बाधित करते हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं हकि हमारे आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस सिस्टमों में भावी तकनीक भी जेंडर-पूर्वाग्रही हो सकती है। हमारे समाज में व्यापत जेंडर पूर्वाग्रह एआई निर्णय-प्रक्रिया में भीा हो सकते हैं जो वर्तमान असमानताओं को और मजबूत करेंगे। यदि हम ज्यादा समतापूर्ण समाज चाहते हैं तो हमें मूलभूत स्तर पर अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है ताकि महिलाओं का समावेशन केवल प्रतीकात्मक न होकर एक ढांचागत व टिकाऊ प्रतिबद्धता बने जिसका विस्तार राजनीति, बिजनेस, प्रशासन तथा महिला-नीत विकास व परिवर्तन तक जाए।

सरकार को महिला आरक्षण कानून का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। कंपनियों को कोटा भरने से आगे बढ़ कर नेतृत्वकारी भूमिकाओं में महिलाओं की पदोन्नति पर निगरानी करनी चाहिए। निवेशकों और वेंचर पूंजीपतियों को अपने पूर्वाग्रहों को संबोधित कर महिला उद्यमियों को समुचित अवसर देना चाहिए। शिक्षा और कौशल-प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लड़कियों का सशक्तीकरण होना चाहिए ताकि वे भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्वकारी भूमिकायें निभा सकें।

यह भी जरूरी है कि एक समाज के रूप में हम ऐसा परिवेश बनाएं जहां महिलायें सुरक्षित अनुभव करें तथा कार्यस्थल पर, राजनीति में व सार्वजनिक स्थलों पर उनको समर्थन मिले। यौन उत्पीड़न तथा कार्यस्थल पर भेदभाव को कठोर विधिक संरक्षण तथा जीरो-टालरेंस नीतियों से समाप्त कर जन प्रतिनिधियों को ये मूल्य प्रकट करने चाहिए। महिला मुद्दों को हाशिये पर धकेलने या दोयम दर्जे का समझने की प्रवृत्ति के बजाय उनको नीति निर्माण व प्रशासन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। इस महिला दिवस पर हमें प्रतीकात्मक संकेतों से आगे बढ़ना चाहिए। समय आ गया है कि इन संख्याओं को व्यावहारिक कार्रवाई में बदला जाए तथा लफ्फाजी से आगे बढ़ कर ऐसी दुनिया बनाई जाए, जहां महिलायें जीवन के हर क्षेत्र में समान साझीदार बनें।

बलात्कार पीड़ितों को त्वरित न्याय जरूरी

> "यौन हिंसा के पीड़ितों को सिर्फ़ कानूनी न्याय से ज़्यादा की ज़रूरत है। उन्हें अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए समग्र सहयोग की ज़रूरत है।"

योगिता भयाना
(लेखिका, बलात्कार पीड़ित्त एक्टिविस्ट हैं)

भारत में यौन हिंसा के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हमारे देश में हर महिला को सुरक्षा, सम्मान और न्याय का मौलिक अधिकार है। फिर भी, यौन हिंसा की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जो हमारे सामाजिक ढांचे में गहरी जड़ें जमाए बैठी चुनौतियों को उजागर करती हैं। हमें ऐसे अपराधों को रोकने और एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए निर्णायक और समाधान-उन्मुख कदम उठाने चाहिए जहां महिलाएं और बच्चे वास्तव में सुरक्षित हों।

पारी फाउंडेशन के संस्थापक के रूप में, मैंने अपना जीवन बलात्कार और यौन हिंसा के पीड़ितों की वकालत करने के लिए समर्पित कर दिया है। 16 दिसंबर, 2024 को, पारी ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम पर पहली बार राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करके एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। इस ऐतिहासिक घटना ने यौन हिंसा से निपटने के हमारे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिसमें नीति निर्माताओं, कानूनी विशेषज्ञों, नागरिक समाज संगठनों, शिक्षकों और पीड़ितों को रोकथाम, प्रतिक्रिया और पुनर्वास के लिए ठोस उपायों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया गया। इस पहल के केंद्र में आगाज का शुभारंभ था, जो लिंग आधारित हिंसा को संबोधित करने के लिए एक व्यापक, समाधान-संचालित दृष्टिकोण पर केंद्रित एक कार्यक्रम था।

सुधार के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक शिक्षा है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों को लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। लैंगिक समानता, सहमति और दर्शकों के हस्तक्षेप के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए नियमित रूप से अनिवार्य कार्यशालाएँ और सेमिनार आयोजित किए जाने चाहिए। कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूल और कॉलेज कर्मचारियों के लिए यौन उत्पीड़न की रोकथाम प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए, जबकि यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा प्रशिक्षण सभी शिक्षकों और प्रशासकों के लिए एक आवश्यकता होनी चाहिए, जिससे उन्हें बच्चों की प्रभावी रूप से सुरक्षा करने के लिए ज्ञान से लैस किया जा सके। सिर्फ़ नीतियों से परे, स्कूलों को अपने पाठ्यक्रम में लैंगिक अध्ययन और भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण को शामिल करना चाहिए, जिससे युवा दिमागों को रिश्तों पर सम्मानजनक और स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिले। डिजिटल सुरक्षा शिक्षा भी महत्वपूर्ण है, जिससे छात्रों को साइबरस्टॉकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न और डिजिटल सहमति के जोखिमों को समझने में मदद मिले। यौन हिंसा से निपटने के लिए आपराधिक मनोविज्ञान और मीडिया के प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। यौन अपराधियों की प्रेरणाओं, ट्रिगर्स और व्यवहार पैटर्न की जांच करने के लिए शोध का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे लक्षित रोकथाम रणनीतियों को विकसित करने में मदद मिले। मीडिया द्वारा लैंगिक गतिशीलता के चित्रण का भी आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, साथ ही जिम्मेदाराना कहानी कहने को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने चाहिए जो विषाक्त मर्दानगी और हानिकारक रूढ़ियों को चुनौती देते हैं।

इसके अतिरिक्त, यौन हिंसा की समाचार रिपोर्टिंग में सुधार की आवश्यकता है। सनसनीखेज या असंवेदनशील कवरेज अक्सर पीड़ितों को फिर से पीड़ित बनाता है और बलात्कार की संस्कृति को मजबूत करता है। मीडिया को मामलों की रिपोर्टिंग में नैतिक दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए, ताकि पीड़ितों की पहचान और अधिकारों की रक्षा हो सके।

यौन हिंसा के पीड़ितों को सिर्फ़ कानूनी न्याय से ज्यादा की जरूरत है। उन्हें अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए समग्र समर्थन की जरूरत है। हर शहर, कस्बे और गाँव में बलात्कार संकट केंद्र ([illegible]) स्थापित किए जाने चाहिए, जो पीड़ितों को चिकित्सा, कानूनी, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करें। उन्हें स्वतंत्रता और स्थिरता हासिल करने में मदद करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और शैक्षिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। पीड़ितों को दोषी ठहराने और पीड़ितों को समर्थन और सशक्त बनाने के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। बलात्कार से जुड़ी मिथकों को चुनौती देने, पीड़ितों पर विश्वास करने के महत्व पर समुदायों को शिक्षित करने और हिंसा को रोकने के लिए दर्शकों के हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक अभियान शुरू किए जाने चाहिए। पुलिस सुधार भी उतने ही जरूरी हैं। कानून प्रवर्तन की अक्षमता और असंवेदनशीलता अक्सर पीड़ितों को अपराधों की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित करती है। यौन हिंसा के मामलों को सहानुभूति और दक्षता के साथ संभालने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों के साथ समर्पित आपातकालीन डायल नंबरों पर स्टाफ होना चाहिए। प्रथम उत्तरदाताओं और फोरेंसिक टीमों को साक्ष्य संग्रह, पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के लिए सख्त प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। पुलिस विभागों के भीतर विशेष जांच इकाइयाँ (स्यु) बनाई जानी चाहिए, जिसमें फोरेंसिक विशेषज्ञ, परामर्शदाता और कानूनी सलाहकार शामिल हों, जिन्हें यौन हिंसा के मामलों को संभालने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया हो। सभी पुलिस कर्मियों के लिए अनिवार्य लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण प्रेरण के दौरान और वार्षिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाना चाहिए। कार्यस्थल सभी के लिए सुरक्षा और सम्मान का स्थान होना चाहिए, फिर भी उत्पीड़न और हिंसा जारी रहती है। [illegible] प्रशिक्षण और ऑडिट को सभी संगठनों में सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, ताकि उत्पीड़न विरोधी नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने में उनकी प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए आंतरिक समितियों (आईसी) को वार्षिक ऑडिट से गुजरना चाहिए। महिला मजदूरों और निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष सुरक्षा शुरू की जानी चाहिए, जिससे सुरक्षित कार्य स्थितियों, कानूनी सहारा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। बेघर महिलाओं और बच्चों के लिए आश्रय गृह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सके। कार्यस्थलों को सुरक्षित और आरामदायक वातावरण प्रदान करना चाहिए।

आप की बात

जन औषधि योजना

भारत सरकार की जन औषधि योजना से आम जनता के औषधियों पर होने वाले खर्च में काफी कमी आई है। औषधि निर्माताओं द्वारा उत्तम गुणवत्तापूर्ण औषधियां प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों पर अत्यन्त कम मूल्य में उपलब्ध हैं। भारत सरकार आयुर्वेद को भी प्रोत्साहित कर रही है किन्तु दुर्भाग्य से अच्छे निर्माताओं द्वारा निर्मित आयुर्वेद औषधियों के बहुत अधिक मूल्य के कारण सामान्य उपभोक्ता इनका लाभ उठाने में असमर्थ हैं। अधिक उपयोग वाले शास्त्रीय आयुर्वेद योगों को अच्छे निर्माताओं द्वारा निर्मित करवा कर न्यूनतम मूल्य पर जन औषधि केन्द्रों पर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। इससे जनसामान्य में आयुर्वेद के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आयुर्वेद विशेषज्ञों से ऐसी औषधियों की सूची सरलता से बनवाई जा सकती है। जन औषधि केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय स्वागत योग्य है। लेकिन इसके साथ-साथ एलोपैथिक डाक्टरों व अस्पतालों द्वारा मरीजों को जेनेरिक नामों से दवा के पर्चे देना भी अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि वे आसानी से जन औषधि केन्द्रों से दवायें खरीद सकें। देश में आयुर्वेद की लोकप्रियता बढ़ाने तथा जनता को यथासंभव स्वास्थ्यरक्षा में आत्मनिर्भर बनाने हेतु व्यापक स्वास्थ्य शिक्षण अभियान चलाने की भी जरूरत है।

– **जय प्रकाश गुप्त**, अम्बाला

महिला सशक्तीकरण

महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में एक दिलचस्प मामला सामने आया है जहां महिला प्रतिनिधियों के बदले उनके पतियों ने पद की शपथ ली और अपना स्वागत करवाया। 6 महिला पंचों की जगह उनके पतियों को पंचायत सचिव ने शपथ दिलाई। यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में महिला सशक्तीकरण की दिशा में बढ़ रहे हैं? सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरक्षण और अन्य प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन फिर भी अधिकांश महिला प्रतिनिधियों का सारा कामकाज पति ही देखते हैं और जनता भी पतियों के पास ही काम करवाने जाती है। इस प्रकरण से स्पष्ट है कि हमारे समाज में अभी भी पितृसत्तात्मक मानसिकता हावी है। महिलाओं को घरेलू कामों तक सीमित और राजनीति को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है। हालांकि, महिलाएं राजनीति में अपनी भूमिका निभा रही हैं और सफलता प्राप्त कर रही हैं। कई महिलाएं मुख्यमंत्री और मंत्री के पदों पर आसीन हुई हैं। इसलिए हमें महिला सशक्तीकरण के लिए काम करने वाले सभी व्यक्तियों और संगठनों को सलाम करने के साथ ऐसी विकृतियां दूर करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

– **मधु सुभाष बुड़ावन वाला**, रतलाम

चीन की अपील

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत से अपील की है वो ट्रम्प के टैरिफ या व्यापार युद्ध से जूझने एवं लड़ने के लिए चीन के साथ एक मंच पर आये। भारत और चीन को सबसे बड़ा पड़ोसी बताते हुए वांग यी ने कहा कि चीन का मानना है कि दोनों को साझेदार होना चाहिए और एक दूसरे की सफलता में योगदान देना चाहिए। ड्रैगन और हाथी के सहयोगी बनने से दोनों पक्षों को लाभ होगा। भारत के साथ सहयोग की इच्छा जाहिर करते हुए चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि आधिपत्यवाद और सत्ता की राजनीति का विरोध करने में अग्रणी भूमिका निभाने की जिम्मेदारी हमारी है। जब चीन और भारत हाथ मिलाएंगे तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अधिक लोकतंत्र और एक मजबूत वैश्विक दक्षिण की संभावनाएं बेहतर होंगी। उन्होंने याद दिलाया कि यह चीन.-भारत राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का साल है। बदली परिस्थितियों में चीन भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार दिखता है, लेकिन भारत का अतीत के कड़वे अनुभवों से बाहर निकला आसान नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चीन भारत के साथ अपने मतभेदों व सीमा समस्या का न्यायपूर्ण हल करने के लिए तैयार है या यह अपील केवल एक बयानबाजी है?

– **जंग बहादुर सिंह**, जमशेदपुर

विदेश मंत्री की सुरक्षा

ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों की निष्क्रियता के चलते भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर की यात्रा के दौरान खालिस्तानी अलगाव और आतंकवाद की झलक फिर नजर आई। एक उच्चस्तरीय राजनयिक के सामने उसके देश के राष्ट्रीय झंडे को फाड़ने की घटना अत्यन्त अपमानजनक व निंदनीय है। इस घटना से ब्रिटेन की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते है। वैसे खालिस्तानी तत्वों का ब्रिटेन में बढ़ता दुस्साहस कोई नई बात नही है। खालिस्तानी समर्थकों की अलगाववादी गतिविधियां कई बार ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में नजर आई हैं। ब्रिटेन ने इस घटना की निंदा करके औपचारिकता निभाई है लेकिन केवल निंदा करना ही काफी नहीं है। ब्रिटेन में काफी लंबे समय बाद लेबर पार्टी की सरकार आई है। ऐसे में यदि वह अपने देश को अलगाववादी व अतिवादी तत्वों का अड्डा बनने देती है तो यह लेबर पार्टी तथा स्वयं ब्रिटेन के लिए भी ठीक नहीं होगा। ब्रिटिश नेताओं को समझना चाहिए कि लोकतंत्र का अर्थ भीड़तंत्र या अराजकता नहीं हो सकता है। भारत-ब्रिटिश संबंधों के लिए ऐसी घटनायें हानिकारक हो सकती हैं।

– **अमृतलाल मारू**, इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते है।

16 प्रतिशत योगदान अकेले अमेरिका का है संयुक्त राष्ट्र के कुल बजट में वर्तमान में, जबकि नाटो के वित्तपोषण का 22 प्रतिशत से अधिक योगदान भी अमेरिका ही देता है। अमेरिका इनमें कटौती कर रहा है, जिसका दुष्प्रभाव इन दोनों संगठनों पर पड़ सकता है।

आजकल

अमेरिकी नीतियों में बदलाव का असर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लिए जा रहे कई नीतिगत निर्णयों ने अंतरराष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की भूमिका पर नए सिरे से बहस को जन्म दिया है। वैश्विक संस्थाओं की मदद रोकने, कठोर टैरिफ लगाने और सैन्य गठबंधनों की समीक्षा करने से लेकर इन निर्णयों के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जैसे-जैसे दुनिया इस नई वास्तविकता के साथ अनुकूलन कर रही है, यह आशंका बलवती हो रही है कि क्या अमेरिका अपनी आत्मनिर्भरता को और मजबूत कर रहा है? ऐसे में भारत के लिए भी चुनौतियां हैं, परंतु इसमें एक अवसर भी है

गजेंद्र सिंह
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार

अमेरिका की बदलती व्यापारिक नीतियों का दुष्प्रभाव भारत पर भी दिख सकता है। फाइल

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद से कई प्रकार के नीतिगत बदलाव होते दिख रहे हैं। इस क्रम में पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआइडी) के लिए धन कटौती का निर्णय ''अमेरिका पहले'' रणनीति के तहत उचित ठहराया गया। सरकार ने डब्ल्यूएचओ द्वारा स्वास्थ्य संकटों के प्रबंधन पर सवाल उठाए और यूएसएआइडी के विदेशी सहायता खर्च पर संदेह व्यक्त किया। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने प्रमुख व्यापारिक भागीदारों पर महत्वपूर्ण टैरिफ लागू करके व्यापार तनाव को बढ़ा दिया है। इस वर्ष के आरंभ में अनुचित व्यापार प्रथाओं का हवाला देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन से होने वाले सभी प्रकार के आयात पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसे बाद में 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा, कनाडा और मैक्सिको से आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाए गए।

वैश्विक दुष्प्रभाव : इन उपायों का आर्थिक प्रभाव गंभीर रहा है। प्रतिशोधात्मक टैरिफ ने आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित किया, उत्पादन लागत बढ़ाई और विशेष रूप से विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में रोजगार के नुकसान का कारण बना। अमेरिकी बजट कार्यालय ने अनुमान लगाया कि व्यापार युद्ध ने औसत अमेरिकी परिवार को उच्च उपभोक्ता कीमतों के कारण प्रति वर्ष अतिरिक्त 1,277 डालर खर्च करने पड़े। एल्युमीनियम उद्योग में 20 हजार प्रत्यक्ष और 80 हजार परोक्ष नौकरियों के नुकसान की आशंका है। वित्तीय बाजारों ने भी नकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

यूक्रेन में अमेरिका की स्थिति एक अन्य विवादस्पद मुद्दा रहा है, जहां ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य समर्थन के दीर्घकालिक लाभों पर सवाल उठाए। जबकि अमेरिका ने 2022 में यूक्रेन को 44 अरब डालर की सैन्य सहायता प्रदान की, नए प्रशासन ने यूरोपीय मित्रों पर वित्तीय बोझ अधिक डालने का प्रयास किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति की रूस के साथ शांति वार्ता में प्रतिबद्धता से असंतोष व्यक्त करते हुए यूक्रेन को सभी अमेरिकी सैन्य सहायता पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी। वहीं दूसरी ओर, अमेरिका में नाटो और संयुक्त राष्ट्र से धन कटौती या निकासी की अटकलें बढ़ रही हैं। अमेरिका वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कुल बजट का 16 प्रतिशत और नाटो के प्रत्यक्ष वित्तपोषण का 22 प्रतिशत से अधिक योगदान देता है। इन योगदानों में कमी दोनों संगठनों की प्रभावशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। अमेरिका द्वारा नाटो और संयुक्त राष्ट्र से धन कटौती के संभावित परिणाम गंभीर और बहुआयामी हो सकते हैं।

भारत पर दुष्प्रभाव : अमेरिका की बदलती नीतियों का भारत पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। चीन और अन्य देशों पर लगाए गए टैरिफ से भारत के लिए ''चाइना प्लस वन'' रणनीति के तहत वैश्विक आपूर्ति शृंखला में अपनी स्थिति मजबूत करने का सुनहरा अवसर मिला है। विशेष रूप से इलेक्ट्रानिक्स, फर्मास्युटिकल्स और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में भारत विनिर्माण हब के रूप में उभर रहा है। भारत की ''आत्मनिर्भर भारत'' पहल अमेरिका की ''अमेरिका पहले'' नीति के समानांतर चल रही है, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक समझ का एक नया आधार तैयार हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती क्षमताएं अमेरिका को अपने हितों की रक्षा के लिए भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं।

वैश्विक संस्थाओं में अमेरिका की कम होती भूमिका से भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का दावा मजबूत हो रहा है, जबकि जी-20, ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों में भारत की भूमिका और महत्व बढ़ रहा है। वैसे अमेरिकी प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियों से भारतीय आइटी सेक्टर, फार्मास्युटिकल्स व आटोमोबाइल निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। एच-1बी वीजा पर कड़े नियम भारतीय आइटी कंपनियों और प्रवासी श्रमिकों को प्रभावित कर सकते हैं।

बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत को अपनी विदेश और व्यापार नीति को पुनर्परिभाषित करना चाहिए। भारत को अमेरिका के साथ संबंधों को बनाए रखते हुए रूस, यूरोपीय संघ, जापान और अन्य एशियाई देशों के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को विविधता देनी चाहिए। ''मेक इन इंडिया'' और ''आत्मनिर्भर भारत'' जैसी पहलों को और मजबूत करके भारत ग्लोबल वैल्यू चेन में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। डिजिटल इकोनमी, हरित ऊर्जा व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे भविष्य-उन्मुख क्षेत्रों में निवेश से भारत वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है। दक्षिण एशिया व हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका मजबूत करके भारत क्षेत्रीय स्थिरता-समृद्धि में योगदान दे सकता है।

भारत के लिए अवसर : अमेरिका की वर्तमान नीतियों से वैश्विक परिदृश्य में जो बदलाव आ रहे हैं, उनमें भारत के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों निहित हैं। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है कि वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और बढ़ती आर्थिक शक्ति के आधार पर वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरे। अमेरिका के ''अमेरिका पहले'' दृष्टिकोण ने वैश्विक नेतृत्व में जो रिक्तता पैदा की है, उसे भरने के लिए भारत अपनी सभ्यतागत मूल्यों पर आधारित 'विश्व बंधुत्व'' की अवधारणा के साथ आगे बढ़ सकता है। भारत की प्राचीन दार्शनिक विरासत ''वसुधैव कुटुंबकम्'' की भावना के साथ, भारत वैश्विक शांति, सहयोग और समृद्धि के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त कर सकता है। भारत के पास इस परिवर्तनशील वैश्विक व्यवस्था में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने का अवसर है- एक ऐसी पहचान जो न तो अमेरिकी एकाधिकार के युग की पुनरावृत्ति है और न ही नव-शीत युद्ध की ओर अग्रसर है, बल्कि एक नई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण है जिसमें समानता, न्याय और आपसी सम्मान के सिद्धांत सर्वोपरि हों।

कितनी टिकाऊ होगी ट्रंप और पुतिन की मैत्री

रथोत्तम शुक्ल
पूर्व प्रशासनिक अधिकारी

विश्व में अब तक दो परस्पर विरोधी ध्रुवों पर खड़े रहे अमेरिका और रूस, डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनते ही एक मैत्री धुरी बनाते दिख रहे हैं। यूक्रेन-रूस युद्ध को लेकर ट्रंप द्वारा अपनाए गए आश्चर्यजनक रुख से तो यही प्रतीति हुई है। इस प्रकरण में अभी तक रूस को आक्रमणकारी मानकर यूक्रेन को जबरदस्त सामरिक सहायता देने वाले अमेरिका के सुर बदल गए हैं और उसने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन संबंधी रूस की ही भाषा वाला प्रस्ताव पारित करा लिया है। वह इस युद्ध के लिए यूक्रेन को ही दोषी मानने लगा है और ब्लैकमेल कर रहा है। अलबत्ता उसके चिर सहयोगी ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोपीय देश इस सब में उसका साथ छोड़ चुके हैं तथा उत्तर अटलांटिक सामरिक संधि (नाटो) में भी स्पष्ट दरार आ गई है। फ्रांस तो मुखर भी हुआ है और रूस को कड़ा संदेश देने के लिए जर्मनी में परमाणु शक्ति संपन्न राफेल तैनात करने जा रहा है। अब यह देखना है कि क्या यह ट्रंप पुतिन मैत्री टिकाऊ होगी? उत्तर है, 'शायद नहीं'।

वस्तुतः अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भावावेश, सनक या रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा ट्रंप पर किए गए उपकार के बदले भले ही यह नीति अपना रहे हैं, किंतु वहां की जनता इसे अनुमोदित नहीं करेगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा यूक्रेन को दी गई सहायता में ट्रंप की पार्टी के सांसद भी समर्थन करते रहे हैं। देर-सवेर वहां की जनता इस बिंदु पर अवश्य आंदोलित होगी। ब्रिटेन व पश्चिम यूरोप की दोस्ती छोड़ना तथा नाटो से अलग होकर कम शक्तिशाली बन जाना ट्रंप भी पसंद नहीं करेंगे। अभी तो इजरायल भी अमेरिका के साथ रूस के समर्थन में उतर चुका है, किंतु क्या ईरान और फलस्तीन तथा अन्य मुस्लिम लाबी से उसकी शत्रुता खत्म हो जाएगी, नहीं। यह असंभव है। तब अमेरिका अपने शत्रु ईरान की तरफ तो नहीं ही खड़ा होगा और रूस-ईरान मैत्री भी समाप्त होना आसान नहीं है। ऐसे में कौन किस तरफ जाएगा?

चीन से रूस के संबंध घनिष्टतम और चिरकालीन हैं। चीन प्रसारवादी है और ताइवान हड़पने की फिराक में है। यदि वह ऐसी कोशिश करेगा, तो क्या अमेरिका पुरुषार्थहीनता का परिचय देकर यह होने देगा? यदि नहीं, तो क्या रूस चीन को छोड़कर अमेरिका के पाले में खड़ा होगा? यह भी संभव नहीं है। उत्तर कोरिया और अमेरिका परस्पर शत्रु हैं। चीन और रूस उत्तर कोरिया के मित्र। उत्तर कोरिया परमाणु बम बनाएगा और जापान, दक्षिण कोरिया को आंख दिखाएगा, तो क्या ट्रंप टुकुर टुकुर देखेंगे? नहीं देख पाएंगे। रूस भारत का चिर मित्र है और भारत भी गाढ़े समय में रूस का साथ देता रहा है। ट्रंप मोदी से चिढ़े हैं और अपने शपथ ग्रहण समारोह से लेकर अप्रवासियों की वापसी तक भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस को यह पसंद नहीं आएगा और मतभेद होंगे।

तमाम वैश्विक मुद्दों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि यह ट्रंप-पुतिन मैत्री चिरस्थायिनी होगी। फिर भी सावधानी के तौर पर ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप को एक अलग सामरिक एवं व्यापारिक धुरी बना लेना चाहिए और इसमें यदि भारत भी शामिल हो जाए, तो यह एक तृतीय बड़ी शक्ति उभरेगी, जो दुनिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने और शांति कायम रखने में सहायक होगी।

खरी-खरी

होली वाले मास्टर जी

सुनील जैन राही

होश संभालने के बाद होली पहला त्योहार था जो दिल से खेलना शुरू किया। जब जिसे चाहा रंग दिया। जिससे दुश्मनी निकालनी हो, उसे होली पर देख लिया। झम्मन के नाम से गांव में दबदबा था, उसमें हर कोई दबा-दबा नजर आता। खुराफात ऐसी कि कोई कल्पना नहीं कर पाता। पता नहीं कब किसकी खटिया खड़ी हो जाए।

गांव के स्कूल में गणित के नए मास्टर जी का आगमन हुआ। गणित की तरह मास्टर जी भी समझ में नहीं आ रहे थे। ज्यादा तीन पांच करते तो क्लास से नौ दो ग्यारह कर देते। होली पर मास्टर जी के लिए मास्टर प्लान बनाया गया। लेकिन समस्या यह कि शेर के गले में घंटा कौन बांधे। सभी की हालत खराब थी। ऐसा कोई न था जो मास्टर जी के हत्थे न चढ़ा न हो। जिसकी नहीं उतरी वे दूसरों की आरती देख घबरा चुके थे। गणित के मास्टर के नाम से बच्चे नींद में पहाड़े बोलकर सुनाते।

झम्मन चाहे कितनी खुराफात कर ले, लेकिन किसी का अपमान नहीं कर सकता। इसीलिए सब दिल से प्यार करते थे। नए मास्टर जी का खौफ झम्मन को भी था। डर यह था कि अभी तक जमी जमाई दुकान कहीं बंद न हो जाए। फिर भी होली की सुबह सभी को इकट्ठा किया। पंसारी की दुकान से सामान लिया, दो-चार को साथ लिया। धीरे-धीरे कारवां बढ़ता गया। दो के चार और चार के आठ होते गए। अब झम्मन ने मास्टर जी का दरवाजा खटखटाया। मास्टर जी बड़े रुतबे से कुर्ता पाजामा में निकले। भीड़ देख तमतमा गए। गरजे-बरसे, गणित की भाषा में सबको समझाया। लेकिन वानर सेना के आगे किसकी चलती है जो उनकी चलती। सबने मिलकर गुलाल से सराबोर कर दिया। मास्टर जी ने जोर का ठहाका लगाया, सभी चौंक गए। मास्टर जी बोले, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हारे लिए मिठाई का इंतजाम किया है।

मास्टर जी छत पर गए और तीन बाल्टियों में घुला रंग बच्चों पर उड़ेल दिया। सब सोच में थे, जो इतना कठोर दिखाई देता है इतना कोमल होगा? कुछ ही दिनों में मास्टर जी का असली नाम तो सब भूल गए, नया नाम पड़ गया- नारियल वाले मास्टर जी, ऊपर से कठोर, भीतर से नरम।

पोस्ट

गुजरात में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में राहुल गांधी कह रहे थे कांग्रेस के कई नेता भाजपा वालों से मिले हुए हैं और हैरानी की बात यह रही कि जब वह ऐसा कह रहे थे तब सामने बैठे कांग्रेसी ठहाके लगा रहे थे। गजब ही मामला है।

मीनाक्षी जोशी@IMinakshiJoshi

बिहार में कांग्रेस और राजद साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में फिर सवाल उठेंगे कि दिल्ली में कांग्रेस ने समझौता क्यों नहीं किया? इसका जवाब यही है कि राजद ने बिहार के बाहर जाकर कभी भी कांग्रेस का वोट काटने की कोशिश नहीं की, जैसा केजरीवाल ने गोवा, गुजरात और हरियाणा में किया था।

आदेश रावल@AadeshRawal

हिंदी में जो एकत्वकारी तत्व है, वह किसी अन्य भारतीय भाषा में नहीं है। भले ही इससे कोई दुखी हो, मन में जलन का भाव पाले या इस पर राजनीति करे, लेकिन इसने लोगों को जोड़ा ही है। सिर्फ द्रमुक जैसी मानसिकता वाले दलों को लगता है कि इसने लोगों को तोड़ा है।

सुशांत झा@jhasushant

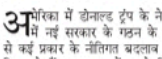

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या ट्रंप की बयानबाजी भारत-अमेरिका के रिश्ते बिगाड़ सकती है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या अमेरिका के टैरिफ वार के बीच चीन के मित्रता प्रस्ताव पर भारत को भरोसा करना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

डर के मारे ट्रंप के चीन सुधारे बुद्धि,
दुनिया के महौल की हो जाएगी शुद्धि।
हो जाएगी शुद्धि न होगा कोई झगड़ा,
तिब्बत-ताईवान खत्म समझो सब लफड़ा।
यदि आ जाय दबंग सामने तो सब हारे,
सुधरेगा अब चीन ट्रंप के डर के मारे!

- ओमप्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश डायरी

बसपा की उलट-पलट में लाभ-हानि देखते विरोधी दल

अजय जायसवाल
राज्य ब्यूरो प्रमुख, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले चार दशक से 'हाथी' की चाल का अपना असर रहा है। हाल के वर्षों में उसकी ताकत जरूर घटी है, लेकिन राजनीतिक प्रभाव कायम है। बीते कुछ चुनावों में सत्ताधारी भाजपा की बड़ी विजय के पीछे विरोधी बसपा की दूसरों को हरवाने की इसी खासियत को वजह बताते हैं। पहले लोकसभा और फिर दूसरे राज्यों सहित दिल्ली के आम चुनाव में शून्य पर सिमटने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती के परिवार में मची कलह और पार्टी की गुटबाजी से चौतरफा हलचल मची है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जिस भतीजे आकाश आनंद को साये की तरह अपने साथ रखकर मायावती ने राजनीति का ककहरा सिखाया और पार्टी का नेशनल कोआर्डिनेटर बनाया उन्हें और उनके ससुर पूर्व सांसद डा. अशोक सिद्धार्थ को पिछले दिनों उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। युवा आकाश के खिलाफ अप्रत्याशित कार्रवाई के बाद मायावती ने खुद की सक्रियता जरूर बढ़ाई है, लेकिन बसपा में उथल-पुथल से 'साइकिल', 'हाथ' व 'कमल' सजग दिख रहे हैं। सपा-कांग्रेस जैसी विरोधी पार्टियां तो पूरे घटनाक्रम में अपने लिए बड़ा राजनीतिक अवसर देख रही हैं।

जिस बसपा का 1984 में कांशीराम ने गठन कर राष्ट्रीय स्तर तक की पार्टी बनाया और मायावती ने अपने नेतृत्व में अकेले दम पर वर्ष 2007 में उसकी सरकार बनाई, उसमें पिछले कुछ वर्षों से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के दुर्दिन वर्ष 2012 में सपा के हाथों सत्ता गंवाने से शुरू हुए। मायावती को

मायावती। फाइल

एक दशक पहले वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में तब बड़ा झटका लगा जब मोदी लहर के चलते पार्टी शून्य पर सिमट कर रह गई। फिर वर्ष 2017, वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी कोई कमाल न कर सकी। इस बीच वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने मजबूरी में ही सही, अपने धुर विरोधी सपा से हाथ मिलाया तो बसपा के 10 सांसद जीतने में कामयाब रहे, लेकिन पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव में अकेले उतरने पर 'हाथी' फिर चारों खाने चित हो गया।

पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव के आए नतीजों के बाद तो जैसे पार्टी में भूचाल आ गया हो। अनुशासित मानी जाने वाली बसपा में पहली बार गुटबाजी की बात सामने आई। बसपा प्रमुख ने अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित करने के साथ ही भतीजे आकाश के उत्तराधिकार को लेकर प्रश्न तक खड़े किए। दो मार्च को मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों संग बैठक में खुलकर कहा कि अशोक ने उत्तर प्रदेश सहित देशभर में पार्टी को दो गुटों में बांटकर कमजोर करने का प्रयास किया। आकाश की शादी अशोक की बेटी से हुई है। आकाश पर उनकी पत्नी का जैसा प्रभाव है वह पार्टी के लिए सकारात्मक नहीं है। ऐसे में कांशीराम के बताए रास्ते पर चलते हुए पार्टी के हित में उनको पार्टी की जिम्मेदारियों से बेदखल करने का निर्णय किया। इस पर आकाश ने 'एक्स' पर प्रतिक्रिया दी तो नाराज मायावती ने इसे उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता करार देते हुए पार्टी से ही बाहर कर दिया। आकाश को हटाने के बाद मायावती ने उसके पिता और अपने भाई आनंद कुमार को पहले नेशनल कोआर्डिनेटर का दायित्व सौंपा, लेकिन बाद में उन्हें केवल उपाध्यक्ष ही बनाए रखा है।

मायावती अब अपनी सक्रियता भी दिखा रही हैं। अपने इकलौते विधायक से मिलने उनके आवास पर गईं और कांशीराम जयंती की तैयारियों का जायजा लिया। इतना ही नहीं वह कांग्रेस-सपा के साथ भाजपा पर भी हमलावर हैं। मुस्लिम समाज को फिर से पार्टी की ओर मोड़ने के लिए उन्होंने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार पर मुसलमानों के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया। उत्तराखंड में निजी मदरसों को सील करने की कार्रवाई पर भी निशाना साधा। मायावती की कोशिश यह संदेश देने की है कि उनकी ताकत कायम है और वह पहले की तरह स्वयं ही पार्टी को आगे बढ़ाने में जुट गई हैं। हालांकि, विरोधियों को मायावती की बढ़ती उम्र में बसपा की 'थकान' दिख रही है।

बसपा के उभार से सत्ता से दूर कांग्रेस खुलकर बहुजन का साथ पाने को मैदान में उतर आई है और अपने नेता उदित राज को आगे कर रखा है। उदित राज ने पहले मायावती का गला घोंटने वाला विवादित बयान दिया और फिर आकाश आनंद को कांग्रेस में आने तक का आफर दे डाला। इरादा सपा का भी यही है। पीडीए में 'डी' की मजबूती के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बसपा की कमजोरी से खासतौर से छिटकने वाले वंचितों को अपने पाले में करने का बड़ा अवसर दिख रहा है। दूसरी तरफ भाजपा की नजरें भी बसपा की 'सेहत' पर टिकी हैं, क्योंकि यदि मायावती कमजोर हुईं तो उसे 'त्रिकोणीय मुकाबले' का फायदा आगे के चुनाव में मिलना आसान न होगा।

मंथन

महिला स्वावलंबन की राह

देश में सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाएं बीते दो दशकों में काफी सशक्त हुई हैं, जिनमें राज्य सरकारों का व्यापक योगदान है। विकास के ऐसे माडल के बारे में भी समझा जाना चाहिए

प्रेम प्रकाश
वरिष्ठ पत्रकार

प्रतीकात्मक

भारत में प्राचीन काल से लेकर राष्ट्रीय आंदोलन और आजादी के बाद संवैधानिक लोकतंत्र में महिला सहभाग का संदर्भ भरा-पूरा है। खास तौर पर बीते कुछ दशकों में जब देश की राजनीति और विकास को लेकर समावेशी समझ का जोर बढ़ा हुआ है तो महिला सशक्तीकरण की बात नए सिरे से शुरू हुई है। मौजूदा दौर में केंद्र की योजनाओं की बात छोड़ भी दें तो राज्यों में महिला स्वावलंबन को लेकर महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। राजनीतिक व्याख्याकार भी यह मान रहे हैं कि अब देश की चुनावी राजनीति का सामाजिक आधार बदल गया है। आज महिलाएं इस आधार का बड़ा रकबा घेरती हैं। यह एक ऐसी गुलाबी क्रांति है, जिसमें देश के कई ऐसे प्रदेश आज बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जो विकास के प्रचलित पैमानों पर कमतर आंके जाते थे। देश में बीमारू राज्य की अवधारणा इसी कमतरी का नतीजा रहा।

बीमारू राज्य से जुड़े पूरे संदर्भ का आगाज पिछली सदी के नौवें दशक से शुरू होता है। इस दौरान ही जनसांख्यिकी और आर्थिक नीतियों के विश्लेषक आशीष बोस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक रिपोर्ट सौंपी थी। बोस ने इस रिपोर्ट में देश के चार बड़े राज्यों- बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बताया। परंतु बीते दशकों में लगातार स्थितियां बदल रही हैं। इस दौरान विकास को लेकर न केवल राज्यों का नया चरित्र उभरा है, बल्कि यह भी देखने में आया है कि राज्य सरकारें अपने राजनीतिक स्थायित्व के लिए विकासवादी लीक पर आगे बढ़ रहे हैं। दिलचस्प है कि बीमारू ठहराए जाने वाले राज्य विकास के विभिन्न मोर्चों पर अपने माडल के साथ चर्चा में हैं।

विकास की दृष्टि से इस बदलाव को मौजूदा राजनीतिक संदर्भ में देखें तो इस वर्ष देश में अब केवल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। अगर इस चुनाव को हम दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव की सीध में देखें तो राज्यों के बदले अर्थ चरित्र को समझ सकेंगे। यह एक ऐसा बदलाव है जिससे देश की संघवादी राजनीति का पूरा चरित्र ही बदल गया है। आज जाति और अस्मिता की राजनीति का उत्तर सर्ग विकासवादी तर्कों पर कसा जा रहा है। बात अकेले बिहार की करें तो यह उन राज्यों में शामिल है, जिसके विकास की संभावनाओं पर लंबे समय तक नकारात्मक तरीके से विचार किया गया। परंतु आज सब कुछ वैसा नहीं है, जैसाकि आज से कम से कम दो दशक पूर्व तक था। जिस गुलाबी क्रांति की बात हमने पहले की है, बिहार आज उस क्रांति और बदलाव का एक नया चेहरा है।

बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट में महिलाओं पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सात बड़ी घोषणाएं की हैं जिनमें कन्या विवाह मंडप निर्माण, महिला हाट, जिम आन व्हील, पिंक टायलेट, कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल, पिंक बस और महिलाओं को ट्रेनिंग देना शामिल है। इस तरह की पहल का महत्व तब ज्यादा समझ में आता है, जब हम जेंडर या पिंक बजट की बात करते हैं। बिहार सरकार के तकरीबन तीन लाख 17 हजार करोड़ के बजट को अगर पिंक बजट के फ्रेमवर्क के साथ देखा-समझा जाए तो यह राज्य में महिलाओं की जिंदगी में बड़े बदलाव को रेखांकित करता है।

लैंगिक समानता : अगर यह बात कही जा रही है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के ड्राइवर, कंडक्टर और डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी, तो यह महिला सशक्तीकरण के लिहाज से वाकई बड़ा फैसला है। जो लोग बिहार के जिलों, यहां के विषम भूगोल और परिवहन सेवाओं को लेकर जमीनी समझ रखते हैं, वे समझ पाएंगे कि इससे प्रदेश की महिलाओं को महज रोजगार नहीं मिलेगा, बल्कि लैंगिक समानता का एक नया दौर भी शुरू होगा। पंचायत में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण सबसे पहले देने वाले राज्य में यह नई पहल उस सिलसिले की एक नई कड़ी है, जिसमें बालिका शिक्षा और जीविका योजना जैसी पहल पहले से बदलाव के नए सुलेख साबित हुए हैं।

बात विकास और चुनाव को लेकर एक साथ करें तो इस लिहाज से भी कई बातें देखने और समझने की हैं। इस नई चर्चा और समझ के केंद्र में है नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा। राजनीतिक पंडित भी अब यह कहने लगे हैं कि बिहार में राजनीति को विकास के जिलावार खाके के साथ नीतीश ने नई जमीन तैयार कर दी है।

बदलाव की इस स्वीकृति तक पहुंचते हुए किसी के भी जेहन में बिहार और यहां के लोगों को लेकर बनाई और बिगाड़ी जाती रही छवि और उससे जुड़े घटनाक्रम उमड़ने-घुमड़ने लगेंगे। लिहाजा बेहतर होगा कि जातीय अस्मिता के खूंटे से बंधकर देश की राजनीति और विकास को लेकर नैरेटिव चलाने वाले बौद्धिक अपने पूर्वाग्रहों से आगे निकलें। क्योंकि तभी वे विकसित भारत के निर्माण में राज्यों के योगदान और उनके विकास माडल की अहमियत को समझ सकेंगे।

****

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 10 मार्च, 2025

दैनिक जागरण

धैर्य की शक्ति से कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की जा सकती है

जानी-पहचानी सुस्ती

यह निराशाजनक है कि लंबित आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को अस्थायी न्यायाधीशों को नियुक्त करने की जो अनुमति दी थी, उसके अनुरूप किसी उच्च न्यायालय ने आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं समझी। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की सुविधा करीब चार वर्ष पहले प्रदान की थी, लेकिन कोई प्रगति होते न देख उसने लगभग एक महीने पहले अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी शर्तों में छूट भी प्रदान कर दी थी। यह आश्चर्यजनक है कि इसके बावजूद किसी उच्च न्यायालय ने अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में कोई रुचि नहीं ली। क्या इसका आशय यह है कि उच्च न्यायालयों को लाखों लंबित मामलों का निपटारा करने की कहीं कोई चिंता नहीं। वस्तुस्थिति जो भी हो, यह ठीक नहीं कि लोगों को समय पर न्याय देने के मामले में कहीं कोई उत्साह नहीं दिखाया जा रहा है।

इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश के सभी उच्च न्यायालयों में करीब 62 लाख मामले लंबित हैं। इनमें से 18 लाख मामले आपराधिक हैं। इन्हीं आपराधिक मामलों का निपटारा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति एवं सुविधा प्रदान की थी। उसने यह अनुमति प्रदान करते हुए अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के कई कारण भी बताए थे और यह भी स्पष्ट किया था अगर रिक्त पद स्वीकृत संख्या के बीस प्रतिशत से अधिक हों तो उच्च न्यायालय अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। कोई नहीं जानता कि यह नियुक्तियां क्यों नहीं की गईं, क्योंकि देश का शायद ही कोई उच्च न्यायालय ऐसा हो जहां न्यायाधीशों के पद रिक्त न हों। करीब दो माह पूर्व राज्यसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों में करीब 350 पद रिक्त थे। अकेले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुल 160 में से 70 से अधिक न्यायाधीशों के पद रिक्त थे। इसी तरह की स्थिति अन्य अनेक उच्च न्यायालयों की भी थी। यह पहली बार नहीं है जब उच्च न्यायालयों ने न्याय चक्र को गति देने में उत्साह का प्रदर्शन न किया हो। इसके पहले यह सामने आया था कि उच्च न्यायालय पूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधियों के आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रहीं एमपी-एमएलए अदालतों की अपेक्षित निगरानी नहीं कर रहे हैं। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट और साथ ही केंद्र सरकार यह देखे कि उच्च न्यायालयों से जो कुछ अपेक्षित है, वह क्यों नहीं हो रहा है। इसी के साथ यह भी आवश्यक है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम व्यवस्था में भी सुधार हो, क्योंकि उच्चतर न्यायपालिका में स्थायी न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने में बहुत समय लगता है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि कोलेजियम व्यवस्था अनेक विसंगतियों से ग्रस्त है।

राशि का सदुपयोग करें

झारखंड में मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के तहत एकमुश्त तीन माह-जनवरी, फरवरी और मार्च की राशि मिलने से महिलाएं कई काम कर सकेंगी। भले ही उन्हें योजना की राशि प्रतिमाह नहीं मिल पाई हो, लेकिन यह सच है कि महिलाएं एक साथ तीन माह की राशि 7,500 रुपये का उपयोग और भी बेहतर और जरूरी काम में कर सकेंगी। एक तो इस राशि का उपयोग कर महिलाएं अपने परिवार के साथ होली पर्व पूरे आनंद के साथ मना सकेंगी। दूसरे, महिलाएं इस राशि का उपयोग अपने बच्चों की पढ़ाई में भी कर सकेंगी। इस माह सभी बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं तथा इसी माह परीक्षा का परिणाम आएगा। बच्चे प्रोन्नति पाकर दूसरी कक्षाओं में जाएंगे जिसके लिए उन्हें नई पाठ्य पुस्तकें से लेकर कापी, बैग एवं अन्य आवश्यक जरूरतें पूरी करनी होंगी। महिलाएं उक्त राशि का खर्च बच्चों की इन सामग्री के क्रय में कर सकती हैं। ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि होली त्योहार में कुछ राशि खर्च कर इनके लिए भी राशि बचा कर रखें। जिन लाभुकों का सत्यापन नहीं हो सका है तथा जिनका आधार बैंक खाते से अभी तक नहीं जुड़ा है, उन्हें भी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर शीघ्र राशि का भुगतान हो। यदि कोई महिला सही में इस योजना के लिए आवश्यक अर्हता रखती है तो उसे लाभ मिलना ही चाहिए। साथ ही सभी जिलों में चल रही जांच की प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो। जांच के नाम पर किसी पात्र लाभुक की राशि रोकी नहीं जा सकती है। ऐसा होता है तो यह उनके साथ अन्याय होगा।

> महिलाओं को चाहिए कि होली के त्योहार में कुछ राशि खर्च कर बच्चों के पठन-पाठन के लिए बचा कर रखें

अप्रत्याशित ट्रंप का मुकाबला

शिवकांत शर्मा

ट्रंप के उलटफेर से बन रही बहुध्रुवीय व्यवस्था में भारत को यदि एक शक्ति केंद्र के रूप में उभरना है तो उसे भी वही करना होगा जो चीन ने किया है

अवधेश राजपूत

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोलभाव और अराजक अप्रत्याशितता की कूटनीति से महीने भर में ही 80 वर्ष पुराने विश्वक्रम को छिन्न-भिन्न कर दिया है। यह विश्वक्रम अमेरिका ने ही दूसरे विश्वयुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र और उसकी सहायक संस्थाओं के जरिये स्थापित किया था। नियमबद्ध व्यवस्था पर आधारित इस विश्वक्रम का मुख्य उद्देश्य दूसरे देशों के भूभाग हथियाने की उस साम्राज्यवादी परंपरा को रोकना था जिसमें 1816 से 1945 के बीच दूसरे देशों के भूभाग हथियाने के लिए 150 से अधिक लड़ाइयां लड़ी गई थीं। नए विश्वक्रम में भारत और फलस्तीन के उल्लेखनीय अपवादों को छोड़कर 1945 से अब तक किसी देश के भूभाग को सैन्य शक्ति से नहीं हथियाने दिया गया। इस दौर में अमेरिका ने सैनिक और आर्थिक महाशक्ति का प्रयोग दूसरे देशों में अपनी कठपुतली सरकारें स्थापित करने या सत्ता परिवर्तन कराने में जरूर किया, पर किसी के भूभाग को हथियाने के लिए नहीं। जबकि 1952 में दक्षिण कोरिया और 1990 में कुवैत की प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए कूदकर वैश्विक नेतृत्व की एक मिसाल कायम की।

ट्रंप ने अपने उद्घाटन भाषण में ही संकेत दे दिया था कि वे अपने ही देश द्वारा स्थापित मौजूदा विश्वक्रम को तिलांजलि देकर दुनिया को 1945 से पहले की साम्राज्यवादी व्यवस्था में लौटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था, 'अमेरिका अपनी परिकल्पना एक उभरते हुए देश के रूप में करना चाहेगा-एक ऐसा देश जिसकी समृद्धि बढ़ रही हो, जिसकी सीमाओं का विस्तार हो रहा हो।' अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बाद में उन्होंने दावा किया कि अमेरिका निश्चित रूप से ग्रीनलैंड को डेनमार्क से खरीद लेगा और मध्य अमेरिकी देश पनामा से पनामा नहर वापस लेगा। कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात तो वह अक्सर करते रहते हैं। दो सप्ताह पहले उन्होंने गाजा को लेकर पिछली सदी के सातवें दशक के बेरूत जैसी सैलानी सैरगाह के रूप में उसका विकास करने की बात करके दुनिया को चौंका दिया।

ग्रीनलैंड, पनामा नहर, कनाडा और गाजा में पांव पसारने के ट्रंप के इरादों से विश्व के कुछ दूसरे साम्राज्यवादी तानाशाहों के हौसले भी बुलंद हो रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग नाटकीयता से बदलते विश्वक्रम के इस दौर को खामोशी से देख रहे हैं, लेकिन ताइवान को चीन में मिलाने के उनके इरादे किसी से छिपे नहीं हैं। वह सही मौके की तलाश में हैं। वह दक्षिण चीन सागर में फैले विवादास्पद द्वीपों पर एक-एक करके कब्जा कर चुके हैं और हिंदचीन एवं दक्षिण एशियाई देशों को वे कर्ज और कारोबारी जाल में फंसाने में लगे हैं। राष्ट्रपति पुतिन की तो जैसे लाटरी ही लग गई है। जो लक्ष्य वह तीन साल के युद्ध में लाखों सैनिक और अरबों के हथियार गंवाकर भी हासिल नहीं कर पाए वह ट्रंप के आने और उनके नीतिगत उलटफेर से अनायास ही हासिल होते दिख रहे हैं। वह सोवियत संघ के विघटन को तबाही मानते हैं और यूक्रेन को रूसी प्रभाव क्षेत्र से अलग स्वतंत्र देश मानने को तैयार नहीं हैं। इसीलिए यूक्रेन का नाटो या ईयू सदस्य बनना उन्हें गवारा नहीं। न ही उन्हें यूक्रेन में रूस विरोधी सरकार गवारा है। अमेरिका और नाटो के बीच यूक्रेन को लेकर गहरी दरार पड़ चुकी है और पुतिन को लेकर नाटो के भीतर भी तकरार के आसार से इन्कार नहीं किया जा सकता। ट्रंप युद्ध रुकवाने के लिए बेताब हैं, पर मोहरे पुतिन के पास हैं।

कुछ राजनयिकों और विदेश नीति विशेषज्ञों को लगता है कि ट्रंप यूक्रेन युद्धविराम और रूस के साथ संबंध बहाल करने का यह खेल पुतिन को चीन के प्रभाव क्षेत्र से निकालने के लिए कर रहे हैं ताकि प्रशांत और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते वर्चस्व का मुकाबला किया जा सके। यदि यह सही हो तो यह भारत के भी हित में होगा, लेकिन इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं। सत्ता संभालने के बाद से ट्रंप के बयानों में रूस की तरह चीन को लेकर भी नरमी ही सुनाई दी है। ट्रंप की कूटनीति में मोलभाव के साथ-साथ ट्रंप की निजी पसंद-नापसंद की नीति भी अहम रहती है। उनके बयानों से स्पष्ट हो जाता है कि वह पुतिन और शी दोनों को पसंद करते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को कतई पसंद नहीं करते, क्योंकि जेलेंस्की ने 2019 में अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने वालों का सर्वर हवाले करने और बाइडन तथा उनके बेटे पर जांच बिठाने के ट्रंप के अनुरोध ठुकरा दिए थे। इसलिए वह यूक्रेन की सुरक्षा और अखंडता की परवाह किए बिना युद्धविराम थोपने की जल्दी में हैं। यह एक तीर से दो शिकार करने की नीति है। जेलेंस्की से बदला मिल जाएगा और पुतिन के साथ लाभकारी संबंध बहाल हो जाएंगे।

युद्धविराम और सुरक्षा समझौता होने से रूस-भारत संबंधों को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ चल रहा तनाव भी समाप्त हो जाएगा। भारत को आर्थिक नुकसान होगा। रूस से सस्ते दामों पर तेल मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन उसकी कुछ भरपाई विश्व बाजार में तेल के दामों मे आने वाली गिरावट और रूस के साथ दूसरे क्षेत्रों में व्यापार बढ़ोतरी से हो सकेगी। हालांकि रूस के साथ अमेरिका के संबंध बहाल होने से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी वर्चस्व की रोकथाम के लिए अमेरिका की सक्रियता बढ़ने की आशा करना खुशफहमी ही होगी, क्योंकि ट्रंप के इरादे चीन से टकराव मोल लेने की जगह व्यापार घाटे को कम करने के ज्यादा नजर आते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप के उलटफेर से दुनिया में एक ऐसा विश्वक्रम बनता नजर आता है जिसमें एक या दो की जगह तीन या चार शक्ति केंद्र होंगे। अमेरिका, यूरोप, रूस तथा चीन। कोई देश दूसरे देशों से खरीदे विमानों, मिसाइलों, ड्रोनों और रक्षा सामग्री के बल पर शक्ति का केंद्र नहीं बन सकता। अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन जैसे शक्ति केंद्रों के पास अपनी-अपनी रक्षा निर्माण क्षमता है। ट्रंप के उलटफेर से बन रही बहुध्रुवीय व्यवस्था में भारत को यदि एक शक्ति केंद्र के रूप में उभरना है और चीनी वर्चस्व का मुकाबला अपने बल पर करना है तो उसे भी वही करना होगा जो चीन ने किया है।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)
response@jagran.com

शैक्षणिक छवि की चिंता का समय

ऋषि गुप्ता

केआइआइटी में एक नेपाली छात्रा की मृत्यु चेतावनी है कि भारत अपने संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे

सुनिश्चित करनी होगी छात्रों की सुरक्षा। फाइल

ओडिशा स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट आफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलाजी (केआइआइटी) में नेपाली छात्रा की असामयिक मृत्यु न केवल दुखद और संवेदनशील मामला है, बल्कि यह भारत की शैक्षणिक व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा पर भी गंभीर प्रश्न खड़ा करती है। केंद्र सरकार ने इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है और पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय का भरोसा दिलाया है। इसके बाद करीब 1000 नेपाली छात्र केआइआइटी वापस लौटे हैं, लेकिन यह मामला केवल न्यायिक जांच तक सीमित नहीं रह सकता। इसके दो पहलू हैं, जिन पर भारत के नीति-निर्माताओं को विचार करने की आवश्यकता है। पहला, नेपाल बीते वर्षों में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बदल चुका है। भारत को इन बदलावों का संवेदनशीलता से आकलन करना होगा। दूसरा, यदि भारत को दक्षिण एशिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाना है तो अंतरराष्ट्रीय छात्रों, विशेषकर अपने पड़ोसी और मित्र देशों के विद्यार्थियों के लिए एक सुरक्षित, संवेदनशील और समावेशी शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करना होगा। इस तरह की घटनाएं इन देशों के साथ हमारे रिश्तों में दरार पैदा कर सकती हैं। चीन जैसे देश जो लंबे समय से नेपाली युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे अवसरों का उपयोग भारत की छवि को कमजोर करने और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि भारत अपने शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा और समावेशिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। साथ ही नस्ली, लैंगिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को संस्थागत ढांचे का अभिन्न अंग बनाए, ताकि सभी छात्र भयमुक्त माहौल में शिक्षा प्राप्त कर सकें।

नेपाल भारत का एक खास पड़ोसी देश है। वह चाहे एक साझा संस्कृति की बात हो या सामाजिक और धार्मिक समानता, भाषा की या फिर लोगों के बीच आपसी संबंध की। भारत और नेपाल के बीच सामरिक ही नहीं, बल्कि एक मजबूत साझा सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक, सैन्य, शिक्षा, खुली सीमा और लोगों के बीच पारस्परिक संबंध हैं। शायद यही कारण रहा है कि संबंधों में यदा-कदा मन मुटाव के बावजूद बातचीत का माहौल हमेशा से बना रहा है। पिछले दो दशकों में नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव आए हैं। इसके चलते नेपाल एक संवेदनशील देश बन चुका है। इसका असर भारत-नेपाल संबंधों पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हम इस प्रयास में हैं कि चीन जैसी ताकत नेपाल के रास्ते भारत के राष्ट्रीय हितों को नुकसान न कर सके। एक समय था जब नेपाली छात्रों और कामगारों के लिए भारत ही प्रमुख गंतव्य हुआ करता था। खुली सीमा के कारण भारत आना-जाना न केवल आसान, बल्कि किफायती भी था। भारत सरकार की छात्रवृत्तियां नेपाली विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर खोलती थीं, लेकिन बीते दो-तीन दशकों में यह स्थिति काफी बदल गई है। विशेष रूप से 1996 से 2006 तक चले माओवादी आंदोलन ने नेपाल के राजनीतिक सोच और विदेश नीति को नया स्वरूप दिया है। इसके साथ नेपाल में विदेश में रोजगार और शिक्षा के अवसर प्रदान करने वाली एजेंसियों का उदय हुआ है। एक समय जेएनयू, बीएचयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या पूर्वांचल विश्वविद्यालय नेपाली छात्रों के गढ़ माने जाते थे, जिसने भारत के प्रति नेपाल में एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में मदद की, लेकिन अब वह बदल चुका है। यह बदलाव केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि रोजगार के क्षेत्र में भी दिखता है। आज अधिकांश नेपाली विकसित देशों को लक्ष्य बनाते हैं। ऐसे में भारत के प्रति जनता की राय में बदलाव आया है। इसका बड़ा फायदा चीन उठा रहा है, जो नेपाली छात्रों को लुभाने में लगा है। इसके परिणामस्वरूप भारत और नेपाल के बीच कोई भी राजनीतिक विवाद अब तुरंत इंटरनेट मीडिया पर छा जाता है।

भारत के शैक्षणिक संस्थान न केवल दक्षिण एशिया और अफ्रीका, बल्कि विश्व भर के छात्रों के लिए आकर्षक केंद्र हैं। ये छात्र यहां शिक्षा प्राप्त कर अपने देशों के उच्च पदों पर पहुंचते हैं और भारत के साथ मजबूत राजनयिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के वाहक बनते हैं। भारत की 'साफ्ट पावर' को भी सुदृढ़ करते हैं, लेकिन ऐसी त्रासद घटनाएं भारत की वैश्विक शैक्षणिक छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं और इसके भू-राजनीतिक प्रभाव भी होते हैं। नेपाली छात्रा की दुखद मृत्यु एक चेतावनी है कि भारत अपने शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा, प्रशासनिक संवेदनशीलता और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को प्राथमिकता दे। एक समावेशी और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण न केवल भारतीय छात्रों, बल्कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए भी आवश्यक है, जो भारत को अपनी शिक्षा और भविष्य के निर्माण के लिए चुनते हैं। इस दिशा में दो महत्वपूर्ण सुधार अनिवार्य हैं-पहला, एक उत्तरदायी और संवेदनशील प्रशासनिक तंत्र, जो छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से सुने और उनका समाधान करे। दूसरा, चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दलों की स्थापना, ताकि किसी भी अप्रत्याशित संकट का समय रहते सामना किया जा सके। केवल इसी तरह हम भारत को एक वैश्विक शैक्षणिक केंद्र के रूप में मजबूत कर सकते हैं और उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रख सकते हैं। अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बना सकते हैं।

(लेखक एशिया सोसायटी पालिसी इंस्टीट्यूट, दिल्ली के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

परिवर्तन

दुनिया में हर चीज परिवर्तनशील है। समय, तारे, ग्रह और नक्षत्र भी अपने स्थान पर निरंतर गति करते रहते हैं। इस जगत में परिवर्तन के अलावा कुछ भी स्थायी नहीं है। भले ही कुछ चीजें स्थायी लगती हों, लेकिन ऐसा है नहीं। निरंतरता परिवर्तन के साथ जुड़ी है। परिवर्तन से ही विकास और विकास से ही लोगों के जीवन में प्रकाश होता है। हम एक निरंतर बदलती हुई दुनिया में रहते हैं। मनुष्य का जीवन भी इसी परिवर्तन का हिस्सा है।

हर नदी एक छोटी धारा के रूप में शुरू होती है। फिर उसमें और दूसरी नदियां मिलती जाती हैं और इस प्रकार एक स्रोत से निकली छोटी-सी धारा बड़ी नदी बन जाती है। नदियां अपना रास्ता बनाती हुई आगे निकल जाती हैं और लगातार अपने अंतिम गंतव्य यानी महासागर की ओर बढ़ती जाती हैं। ठीक यही स्थिति मनुष्य के जीवन यात्रा की है। मनुष्य भी कभी रुका नहीं है। शुरुआत से अब तक मानव ने अनगिनत उपलब्धियां हासिल की है। आग से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर किया है। यह निरंतर परिवर्तन का सूचक है। इसलिए मनुष्य को दुख में न ज्यादा दुखी और सुख में न ज्यादा प्रफुल्लित होना चाहिए, बल्कि दोनों ही परिस्थितियों में इंसान को चाहिए कि वह संतुलन बनाकर रखे। अल्पकालीन क्षणभंगुर सुख और दुख के लिए हमें कभी विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी अल्पकालिक एवं अस्थायी हैं। समय हर एक चीज का मूल्यांकन सही समय पर कर देता है। इसलिए मनुष्य को धैर्य, शांत, मौन एवं एकांत-ये चार गुण अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करना चाहिए।

मानव जीवन में भी ऐसे ही तमाम उतार-चढ़ाव आते-जाते रहते हैं। अगर हम परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते हैं तो सामने परेशानियों का बड़ा पहाड़ नजर आने लगता है। इसलिए जीवन जीने का सही तरीका यही है कि मनुष्य परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाए।

समराज चौहान

युवाओं को कुशल बनाने की चुनौती

ठेंद्रराज सुथार

इंडिया ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स के अनुसार भारतीय स्नातक औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने में पिछड़ रहे हैं

बदलते समय और तकनीकी विकास के साथ उद्योगों की जरूरतें भी बदल रही हैं, लेकिन देश की शिक्षा व्यवस्था इस बदलाव के अनुरूप खुद को ढाल पाने में असमर्थ दिख रही है। हाल में प्रकाशित 'इंडिया ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स-2025' रिपोर्ट यह दर्शाती है कि भारतीय स्नातक औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने में पिछड़ रहे हैं और उनकी रोजगार क्षमता में गिरावट आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में स्नातकों की समग्र रोजगार योग्यता दर 2023 में 44.3 प्रतिशत थी, जो 2024 में घटकर 42.6 प्रतिशत रह गई। यह गिरावट मुख्य रूप से गैर-तकनीकी भूमिकाओं में देखी गई, जबकि तकनीकी क्षेत्रों, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन शिक्षण में सुधार हुआ है, जहां 46 प्रतिशत स्नातक अब योग्य माने जा रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार पुरुष स्नातकों की रोजगार योग्यता दर 43.4 प्रतिशत रही, जबकि महिलाओं की 41.7 प्रतिशत दर्ज की गई। यह अंतर संकेत करता है कि महिलाओं को अभी भी समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। करियर के अवसरों तक सीमित पहुंच, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं तथा तकनीकी कौशल सीखने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। महिलाओं को समान अवसर और प्रशिक्षण दिया जाए तो वे पुरुषों के समान या उनसे बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा नीति में ऐसे बदलाव किए जाएं, जो महिलाओं को सशक्त बनाएं और उन्हें तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल में आगे बढ़ने के अधिक अवसर दें। शिक्षा प्रणाली की संरचना के आधार पर भी रोजगार योग्यता में महत्वपूर्ण भिन्नताएं पाई गई हैं। उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों के स्नातकों की रोजगार योग्यता दर 48.4 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि मध्यम स्तरीय संस्थानों के लिए यह 46.1 प्रतिशत और निम्न स्तरीय शिक्षण संस्थानों के लिए 43.4 प्रतिशत रही। इसका अर्थ यह है कि शीर्ष शिक्षण संस्थानों से स्नातक करने वाले छात्रों को बेहतर रोजगार मिलने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि वे अधिक प्रतिस्पर्धात्मक कौशल से लैस होते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार कार्यस्थलों में केवल तकनीकी दक्षता ही पर्याप्त नहीं है। कंपनियां अब ऐसे स्नातकों को प्राथमिकता दे रही हैं, जिनमें संचार कौशल, समस्या समाधान क्षमता, टीमवर्क और नेतृत्व जैसे गुण भी मौजूद हों। भारतीय स्नातकों में इन क्षमताओं की कमी देखी गई है, जिससे वे उद्योग में प्रतिस्पर्धा करने में पीछे रह जाते हैं। चूंकि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की सीमित पहुंच, प्रशिक्षकों की कमी और तकनीकी शिक्षा की बढ़ती लागत जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। ऐसे में यदि उद्योगों और शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाए, तो इससे स्नातकों की दक्षता में सुधार संभव है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

खतरे में अमेरिका की विश्वसनीयता

'अविश्वनीय साबित होते ट्रंप' शीर्षक से लिखे आलेख में संजय गुप्त ने डोनाल्ड ट्रंप की अस्थिर नीतियों, मनमाने फैसलों और व्यापारिक एवं कूटनीतिक मामलों में उनके अप्रत्याशित रवैये को उजागर करते हुए यह बताया है कि उनका बड़बोलापन अमेरिका की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अनियंत्रित व्यवहार वैश्विक स्थिरता के लिए चुनौती बनता जा रहा है। उनकी व्यापार नीतियां, प्रशासनिक आदेश और कूटनीतिक रवैया न केवल अमेरिका की छवि को आघात पहुंचा रहे हैं, बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन को भी अस्थिर कर रहे हैं। उनकी टैरिफ नीति ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तनाव बढ़ा दिया है। यदि अन्य देश भी इसी राह पर चले, तो वैश्विक आपूर्ति शृंखला बाधित होगी और उपभोक्ताओं को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। भारत के प्रति ट्रंप का रवैया भी अस्थिरता से भरा है। वे भारत को उच्च टैरिफ लगाने वाला देश बताते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक असंतुलन को दूर करने के लिए वार्ता जारी है। अमेरिका, भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और ऐसे में संवाद एवं सहयोग आवश्यक है, न कि दबाव एवं धमकी। ट्रंप की कूटनीति भी अस्थिर है। यूक्रेन संकट में उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं है, जिससे यूरोप की सुरक्षा चिंताएं बढ़ रही हैं। अमेरिका द्वारा पहले सहायता देना और फिर अपने हितों के अनुरूप मुकर जाना, उसकी विश्वसनीयता को कमजोर कर रहा है। विश्व को ऐसे अनिश्चित नेतृत्व के प्रभाव से बचने के लिए बहुपक्षीय सहयोग को प्राथमिकता देनी होगी। व्यापारिक विवादों का हल आक्रामक नीतियों से नहीं, बल्कि समन्वय से निकलेगा। भारत को भी आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि किसी भी देश के मनमाने फैसले से उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित न हो। अमेरिका को यह समझना होगा कि आर्थिक शक्ति केवल संख्याओं से नहीं, बल्कि स्थिरता और सहयोग से बनती है। यदि ट्रंप अपनी नीतियों में संतुलन नहीं लाते, तो अमेरिका का वैश्विक प्रभाव केवल नाममात्र रह जाएगा।

अमन सिंह गौर, बीएचयू

महिलाएं होंगी आत्मनिर्भर

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ एक सराहनीय कदम है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा इस योजना को लागू करने के लिए 5,100 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूरी देने से इस योजना को लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा। दिल्ली प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र व्यक्तियों को वित्तीय सहायता का पारदर्शी, कुशल और निर्बाध वितरण हो। भाजपा की डबल इंजन सरकार द्वारा दिखाए गए लाभ से कमजोर वर्गों की महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा। 2,500 रुपये प्रतिमाह की नियमित पेंशन से बीपीएल महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी द्वारा इस योजना को राजनीतिक नौटंकी कहना, हार की हताशा को प्रदर्शित करने का प्रपंच मात्र है।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

मोहम्मद शमी पर अकारण विवाद

भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने मैच के दौरान मैदान में साफ्ट ड्रिंक क्या लिया, एक मौलाना ने मोहम्मद शमी को इस्लाम का गुनहगार ठहरा दिया। हालांकि कई इस्लामिक विद्वानों ने मौलाना को आड़े हाथ लिया है। मोहम्मद शमी शानदार प्रदर्शन से देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और हार-जीत के फैसले में भी उनकी अहम भूमिका रहती है। धर्म गुरु द्वारा अनावश्यक बयान देते रहेंगे तो खिलाड़ियों का मनोबल भी टूटा है और उनके प्रदर्शन पर इसका प्रतिकूल असर भी पड़ सकता है। इसलिए, हमारे धर्म गुरुओं को अनावश्यक रूप से युवाओं को धर्म आधारित विवाद में नहीं फसाना चाहिए। युवा देश की तकदीर हैं। ये बेहतर शिक्षा प्राप्त करेंगे और स्वास्थ्य रहेंगे तो देश के लिए उपयोगी साबित होंगे। इससे उनमें देश के प्रति भी सेवा भाव रहेगा। देश के युवाओं को भी समझना होगा कि राष्ट्र प्रथम और सर्वोपरि है। बाकी सारी व्यवस्थाएं गौण हैं।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com